

खास खबर

नितिन गडकरी को
बॉम्बे हाईकोर्ट से

राहत

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्टीय मंत्री नितिन गडकरी को बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और अन्य डिजिटल मध्यस्थों को उनके व उनके परिवार के ई20 एथेलिन ब्लॉकिंग प्रोग्राम से जुड़े कथित मानहानिकारक, डीफैक और एआई से तैयार फर्जी कंटेंट को हटाने का अनिवार्य आदेश दिया है। जस्टिस आरिफ डोहरे की एकल पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया कंपनियों और संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिया कि वे गडकरी के ई20 एथेलिन ब्लॉकिंग प्रोग्राम से जुड़े कथित मानहानिकारक, डीफैक और एआई से तैयार फर्जी कंटेंट को हटाने का अनिवार्य आदेश दिया जाए।

25 टन
मिलावटी मसाले
जब्त, 3 गिरफ्तार

हेदराबाद। हेदराबाद में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले गिरोह के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हेदराबाद फूड एक्स्प्रेसन सर्विलंस टीम ने जोधपुरमारी के फूड सेपरी विभाग के साथ मिश्रक राहत के अलग-अलग सामान कारोबारी और प्रोसेसिंग यूनिट्स पर एक साथ छापेमारी की। इस अभियान में कुल 25 टन मिलावटी मसाले जब्त किए गए। इस मिलसिले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किए हैं और उनके खिलाफ तीन अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, यह विशेष अभियान पुलिस से मिली विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया था। लगातार कार्रवाई मसालों में खतरनाक रसायन और औद्योगिक रंग मिलाकर उन्हें बाजार में बेच रहे हैं।

केमिकल लीक से
3 मजदूरों की मौत

यादगिरी। कानाऊक के यादगिरी जिले के कंडेडूर-बडियाल ईस्टर्नपल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में केमिकल रिसक होने से दम घुटने के कारण 3 मजदूरों की मौत हुई। मृतकों की पहचान तेलंगना के महबूबनगर निवासी कटला राणेश और मध्य प्रदेश के कटनी निवासी विक्रम सिंह गौड़ और संजय सिंह गौड़ के रूप में हुई है। हादसे में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के रहने वाले मंचला हेमंत और मंचा शिवकुमार घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने सैलफु प्वांते में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कुछ ना कहना
इंजीनियर के घर से 66
लाख नकद बरामद

भ्रष्टाचारियों का बस
चले तो पेट में भी
रखने लग जायें।



बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

सेंसेक्स	- 78,581.00
निफ्टी	- 24,624.65
सोना	- 1,54,121
चांदी	- 2,40,000
डॉलर	- 95.06

परिसीमन और महिला आरक्षण पर विशेष सत्र की तैयारी, सरकार कर रही मंथन, 16 अगस्त से तीन दिवसीय विशेष सत्र की चर्चा

दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश तेज

रिजिजू ने राहुल और प्रियंका गांधी से की मुलाकात, परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन बिल पर मांगा समर्थन

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयकों को पारित करने की तैयारी में जुटी है। सूर्यो के अनुसार, 13 अगस्त को समाप्त होने वाले मानस सत्र के बाद संसद का तत्काल सत्रावसान (प्रोरोगेशन) नहीं किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर जल्द विशेष सत्र बुलाया जा सके। सूर्यो के मुताबिक सरकार दोनों सदनों में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत सुनिश्चित करने के प्रयास में है। यदि पर्याप्त समर्थन मिल जाता है तो 16 से 18 अगस्त तक तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस बीच संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजू ने बुधवार को लोकरसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन बिल पर समर्थन मांगा है।



50 मिनट तक हुई दोनों के बीच बातचीत

रिजिजू और राहुल गांधी के बीच करीब 50 मिनट तक बैठक चली। बैठक के दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किरन रिजिजू ने संसद में जारी विपक्ष पर चर्चा करने के लिए लोकरसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री से मुलाकात की। विपक्ष ने इस सत्र में परिसीमन विधेयक पारित करने की सरकार को योजना में अड़चन पैदा कर दी है। सूर्यो के अनुसार, गुणमूल काग्रेस और उद्वेग ठाकुर की शिवसेना से दलबद्ध के कारण सदर में मिली नई संख्या के चल पर सरकार को उम्मीद थी कि वह पिछले सत्र में विपक्ष से इस विवादालय विधेयक को पारित चलेगी।

16 से 18 तक विशेष सत्र बनाने की तैयारी

परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयकों को पारित करने की तैयारी में सरकार दोनों सदनों में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत सुनिश्चित करने के प्रयास में है। यदि पर्याप्त समर्थन मिल जाता है तो 16 से 18 अगस्त तक तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूर्यो के अनुसार सरकार ने काग्रेस सहित विपक्षी दलों के सामने विशेष सत्र का प्रस्ताव रखा है। काग्रेस ने इस पर सहयोगी दलों से चर्चा के बाद अपना खस स्थ करके की बात कही है। यदि विपक्ष का पर्याप्त समर्थन मिलता है तो सरकार विधेयकों को आगे बढ़ा सकती है।

एक नया परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा

परिसीमन का अर्थ है लोकरसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का नए सिरे से निर्धारण। इसका उद्देश्य बदलती जनसंख्या के अनुरूप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का संतुलित स्थापित करना होता है। सरकार द्वारा लागू एक प्रस्तावित परिसीमन विधेयक-2026 के तहत एक नया परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा, जो नवीनतम जनगणना के आधार पर लोकरसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन करेगा। यदि विधेयक पारित होता है तो लोकरसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 815 तक बढ़ाई जा सकती है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 35 सीटों का प्रावधान हो सकता है। इस प्रकार कुल लोकरसभा सीटों की संख्या 850 तक पहुंच सकती है। राज्यी और केंद्र शासित प्रदेशों की मिलने वाली सीटों का पुनर्वितरण नई जनसंख्या के आधार पर होगा। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से निर्धारित की जाएंगी।

महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता

सरकार का कहना है कि नए परिसीमन के बाद ही लोकरसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। प्रस्ताव के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें सम्य-सम्य पर बदलती रहेंगी, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके। भारत में लोकरसभा सीटों की संख्या सम्य-सम्य पर बढ़ाई गई। 1952 में 489 सीटों की गई वहीं 1963 में 1961 की जनगणना के आधार पर 522 सीटों की गई। 1973 में 1971 की जनगणना के आधार पर 543 सीटों की गई। इसका बाद 425 प्रतिशत संशोधन के जरिए सीटों के पुनर्वितरण पर कर लगाई गई थी, जिसे बाद में बहाल 2026 तक कर दिया गया। वर्ष 2002 में परिसीमन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किया था, लेकिन लोकरसभा सीटों की कुल संख्या 543 ही बनी रही। यदि सरकार विशेष सत्र बुलाती है और आवश्यक सर्वेधान संशोधन पारित हो जाते हैं, तो देश की चुनौती राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नई जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण, महिला आरक्षण का क्रियाव्यवस्था और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन आगामी आम चुनावों की दिशा और राजनीतिक समीकरणों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि, पिछलाव विशेष सत्र बुलाना और विधेयकों को पेश करने संबंधी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

दुष्कर्म के मामलों में साक्ष्य के आधार पर फैसला दे कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

ने जारी की नई गाइडलाइन

नई दिल्ली। दुष्कर्म और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सुनवाई को अधिक संवेदशील, निष्पक्ष और पौडिता-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनएन) घोषणा ने नई गाइडलाइन जारी की है। यह दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुगमन में तैयार किया गया है, जिनका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में पुरावाओं को समान करना और केवल साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष सुनिश्चित करना है। गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि सुनवाई और फैसला लिखते समय न्यायाधीश पौडिता के चरित्र, पहचान, निजी जीवन, सामानजनक बयाना जाए। गवाहों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो और उन्हें अनवश्यक प्रतीति न कराई जाए। यदि पौडिता चाहे तो वीडियो कॉन्फेंसिंग या इन-कैमरा कार्यावाही जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। गाइडलाइन के अनुसार न्यायाधीश को न्याय व्यवस्था पर परीक्षा बढ़ेगा और अदालतों में लैंगिक संवेदनशीलता को भी मजबूती मिलेगी।

अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से झटका

इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को गुणमूल काग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायरेक्ट हॉन्डर से संसद अभिषेक बनर्जी को आंग के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनकी याचिका भी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सोमनाथ मुखर्जी को एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि पिछली सुनवाई में अभिषेक बनर्जी को पहले कोलकाता के सरकारी एमएफकेएम मेडिकल कॉलेज जाएं अस्पताल के विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सलाह दी गई थी। अदालत ने कहा था कि अस्पताल की रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस मामले में फैसला किया जाएगा।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राहत देने से क्यों किया इनकार?

हालांकि, सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी को और से अदालत को बताया गया कि वह एमएसकेएम अस्पताल नहीं जाएंगे। इसके बाद न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने उन्हें विश्वास कर इलाज करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और पूरी याचिका खारिज कर दी। इससे पहले 20 जुलाई को सुनवाई में हाईकोर्ट ने उन्हें पहले एमएसकेएम अस्पताल से परामर्श लेने को कहा था। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने विदेश जाने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

काँकरोच जना पार्टी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की सरकार को नसीहत

युवाओं की आवाज सुनिए, आक्रामक रवैया नहीं

नई दिल्ली। काँकरोच जना पार्टी (सेजेपी) के संसद चलो प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और कानून-व्यवस्था संभालने वाले एजेंसीओं को महत्वपूर्ण संदेश दिया। अदालत ने कहा कि युवाओं की बात सुनना किसी भी सरकार का सबसे ताकतवर हथियार है और विपक्ष प्रदर्शनों से निपटने में संयम, संवाद तथा काउंटेर्सिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चौक जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बगवती और जस्टिस वी. मोहन को पीठ ने यह टिप्पणी रिटायर्ड एडवोकेटों अधिकारी मनीष कुमार सोलंकी को याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

याचिका में 20 जुलाई को आयोजित संसद चलो मार्च के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को इसी घटनाक्रम से जुड़ी एक अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया है।

मठ के युवाओं को समझाने की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कुछ युवा पंथरवाजी जैसी घटनाओं में शामिल भी हो जाएं, तब भी फैला प्रयास उन्हें समझाने और मुखधारा में वापस लाने का होना चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसे युवाओं को काउंटेर्सिंग की जानी चाहिए, क्योंकि केवल सख्ती से समस्या को प्रभावित नहीं होगा।

पुलिस सव्य से काम ले

लोकतान्त्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। यदि प्रदर्शन के दौरान तनाव की स्थिति बनती है, तो पुलिस और याचिकाएं को अव्यक्त संयम बरतना चाहिए ताकि हालात को न बिगाड़ें।

युवाओं की बात सुनना सबसे प्रभावी तरीका

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि युवा अखिर किस कारण विरोध कर रहे हैं। सैन्य इलाकों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी बाहर भेजे जाने की आवाजों की भी जांच हो रही है।

पीएम मोदी का फेसबुक से वीडियो समेत 9 गिरफ्तार, जंतर-मंतर पर करना चाहते थे आतंकी हमला!

तय समय सीमा में आवश्यक कार्रवाई नहीं की तो उठाए जाएंगे कानूनी कदम

पर सरकार ने जुकरबर्ग को दी मोहलत

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही को लेकर कुछ खस अपनाया है। पीएम मोदी ने बुद्धि एक वीडियो हटाने के मामले के बाद सरकार ने प्रमुख उद्देश्य के कर्तव्यों को सख्त चेतावनी दी है। सरकार ने साफ किया है कि यदि तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब और आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाए तो कानूनी कदम उठाए जाएंगे, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मिलने वाली 'सेफ हॉबर' सुरक्षा समाप्त करने की कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है। सूर्यो के मुताबिक फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को तीन दिन के अंतर्गत स्पष्टीकरण देने, माफी मांगने और आवश्यक कार्रवाई करने का समय दिया है। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री के लिए न्याया जवाबदेह होना होगा। सरकार ने गुणल, यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के समेत सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिया है कि वे बच्चों के यौन शोषण और महिलाओं से संबंधित आपत्तजनक चीजें सामग्री को तीन दिनों के भीतर हटाना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं होने पर संबंधित प्लेटफॉर्मों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संसद को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थानीय समिति की तीन अगस्त को तीन घंटे तक चली बैठक के बाद सफित के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा था कि वेता ने खुद स्वीकार किया है कि पीएम मोदी का वीडियो रात 12:30 बजे से सुबह पांच बजे तक प्लेटफॉर्म पर अनुपलब्ध था। यह बेहद गंभीर मामला है और इस पर मार्क जुकरबर्ग को और से व्यक्तिगत माफी जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि यदि जुकरबर्ग माफी नहीं मांगते हैं तो आईटी अधिनियम के तहत वेता को प्राप् 'सेफ हॉबर' संरक्षण वापस लेने पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्रावधान के तहत सोशल मीडिया नेवंबर और डेसेंटेड प्रथा प्रदान और प्लेटफॉर्म पर थर्ड पार्टी को सामग्री के लिए कानूनन जिम्मेदार नहीं होने।

पुलिस ने पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आइएसआई के शरार पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साक्ष्य का दावा किया है। अनुसर पुलिस के मुताबिक इस मामले में कि अलग-अलग गिरोहों से जुड़े चार नाबालिग सभने ती लोगों को हिस्सा में लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के पास से बोलबल, निस्त्रील, कातरस और अन्य सॉफ्ट्स सामन बरामद हुआ है। जांच में इस नेवटक का कनेक्शन मुहैया करने में भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक का आरोपी अपने साथियों के चले होते कोई वारदात नहीं हो सके वही आरोपी वापस पंजाब लौट आए। अब जांच एजेंसीयां इस वारदात को अंजाम देने की योजना थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसीयां की हथियारों की सफाई और दूसरे अपने संसूचे में सफल नहीं हो सके। अनुसर पुलिस के मुताबिक का आरोपी के आदेशों को अंजाम देने में बड़े आईएसआई हैंडलर से निर्देश मिल रहे थे। पुलिस का दावा है कि जंतर-मंतर पहुंचने के बाद आरोपीयों को स्थानीय स्तर पर मदद और सामग्री उपलब्ध करने की कोशिश की गई थी। वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में भी आए थे, जिसे कथित तौर पर हथियार और विस्फोटक मुहैया करने में भी शामिल किया गया था। पुलिस के मुताबिक का आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े आईएसआई हैंडलर से निर्देश मिल रहे थे। पुलिस का दावा है कि जंतर-मंतर पहुंचने के बाद आरोपीयों को स्थानीय स्तर पर मदद और सामग्री उपलब्ध करने की कोशिश की गई थी। वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में भी आए थे, जिसे कथित तौर पर हथियार और विस्फोटक मुहैया करने में भी शामिल किया गया था। पुलिस के मुताबिक का आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े आईएसआई हैंडलर से निर्देश मिल रहे थे। पुलिस का दावा है कि जंतर-मंतर पहुंचने के बाद आरोपीयों को स्थानीय स्तर पर मदद और सामग्री उपलब्ध करने की कोशिश की गई थी। वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में भी आए थे, जिसे कथित तौर पर हथियार और विस्फोटक मुहैया करने में भी शामिल किया गया था।

सुरक्षा एजेंसीयां की संस्थानों के चलते कोई वारदात नहीं हो सके वही आरोपी वापस पंजाब लौट आए। अब जांच एजेंसीयां इस वारदात को अंजाम देने की योजना थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसीयां की हथियारों की सफाई और दूसरे अपने संसूचे में सफल नहीं हो सके। अनुसर पुलिस के मुताबिक का आरोपी के आदेशों को अंजाम देने में बड़े आईएसआई हैंडलर से निर्देश मिल रहे थे। पुलिस का दावा है कि जंतर-मंतर पहुंचने के बाद आरोपीयों को स्थानीय स्तर पर मदद और सामग्री उपलब्ध करने की कोशिश की गई थी। वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में भी आए थे, जिसे कथित तौर पर हथियार और विस्फोटक मुहैया करने में भी शामिल किया गया था। पुलिस के मुताबिक का आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े आईएसआई हैंडलर से निर्देश मिल रहे थे। पुलिस का दावा है कि जंतर-मंतर पहुंचने के बाद आरोपीयों को स्थानीय स्तर पर मदद और सामग्री उपलब्ध करने की कोशिश की गई थी। वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में भी आए थे, जिसे कथित तौर पर हथियार और विस्फोटक मुहैया करने में भी शामिल किया गया था।

कान्हा से सटे गांवों में टाइगर टेरर, हर दिन दहशत में गुजर रही जिंदगी

महिला की जान लेने के अगले ही दिन, बाघ ने भैंस का किया शिकार, ग्रामीण बोले- 3 वर्षों में हो चुकी है 4 ग्रामीणों की मौत, मुआवजे में देरी से फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, ग्रामीणों ने सुरक्षा बढ़ाने की करी मांग

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।



कान्हा नेशनल पार्क से लगे ग्रामीण अंचलों में लोग, रोजाना बाघ की दहशत में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर है जहां कान्हा से सटे ग्रामों में बाघों की बढ़ती गतिविधियों ने एक बार फिर वन्यजीव-मानव संघर्ष को गंभीर बना दिया है। बीते दो दिनों में झुंड दो घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है। अभी हाल ही में एक बाघिन ने महिला के घर में घुसकर उसका शिकार कर लिया था जिससे महिला की मौत हो गई थी, अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था की, इस घटना के अगले ही दिन गांव के समीप जंगल में घर रही एक भैंस को बाघ ने घटना शिकार बना लिया। लगातार हो रही इन घटनाओं से कुमादेही, परपूर, मालखेड़ी और खापा सहित आसपास के गांवों में भय और दहशत का माहौल है। जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की है।

बाघों की मौजूदगी,लोगों के लिए खतरा

ग्रामीणों का कहना है कि कान्हा प्रबंधन द्वारा एक और आसपास बाघिन के रेस्त्रय की कारवां की गई है, लेकिन दूसरी ओर नई में अन्य बाघों की लगातार बढ़ती मौजूदगी लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। खेतों में काम करने से लेकर पशुधर्मों को चरने और शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलने तक लोग डर के साथ में जीवन बिताने को मजबूर हैं।

भावांतर योजना नहीं, किसानों के साथ विश्वासघात है

सड़क से लेकर सदन तक कॉरेंगे आंदोलन-किसान गर्जना संगठन पद्मेश न्यूज। बालाघाट। मध्य प्रदेश सरकार धान उत्पादक किसानों के साथ एक और बड़ा अन्याय करने की तैयारी में है। भावांतर योजना के नाम पर किसानों को सरकारी खरीदी से दूर कर निजी व्यापारियों के भरोसे छोड़ने की साजिश रची जा रही है कि किसान गर्जना संगठन इस किसान विरोधी योजना का पुनरावृत्ति विरोध करता है और स्पष्ट चेतावनी देता है कि किसी भी कीमत पर किसानों को योगदान नहीं देने दिया जाएगा। प्रदेश के हजारों गांवों में मंडियों का अभाव है। यह भावांतर योजना लाहू तो किसानों को अपनी उख बचने के लिए पट्टा, से 35, 80 से 95 किमीोटर दूर पट्टा बना पड़ेगा (गतिवृद्ध का अतिरिक्त खर्च, समय को बर्बाद और व्यापारियों की मनमानी का पूरा बोझ किसानों पर डाला जाएगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटकर किसानों को खुले बाजार में खुदने के लिए छोड़ना चाहती है। सरकार बाघ कि जब बाघों से सम्पन्न भूमि पर खरीदी को व्यवस्था कर रही है, तो उसे कमजोर करने की जकल क्यों पड़ रही है? आदिार जिसके रखाव में किसानों को व्यापारियों के हवाले किया जा रहा है? किसान इसका जवाब मांग रहा है कि किसान गर्जना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने कहा कि यदि सरकार ने भावांतर योजना के माध्यम से धान खरीदी लागू करने का प्रयास किया, तो पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव आंदोलन होगा। सड़क से लेकर विधानसभा तक किसानों को आवाज बुलंद की जाएगी। किसानों के हितों पर कुठाराघात किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मांग पूरी ना होने सड़क पर उतरेंगे किसान पद्मेश न्यूज। बालाघाट। किसानों से मांग करता है कि धान की खरीदी पूर्व की तरह सरकारी खरीदी केंद्रों पर ही सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक क्षेत्र में पयोग लाइव केंद्र एवं मंडियां स्थापित की जाए (किसानों को व्यापारियों के भरोसे छोड़ने वाला किसी भी व्यवस्था को तत्काल वापस लिया जाए जिसकी को न्यूनतम सम्पन्न मूल्य का पूरा साथ और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।बताया कि यह लाइव किसी संगठन की नहीं, प्रदेश के हर किसान के सम्मान और अधिकार की लड़ाई है।इसलिए किसान जिसान संगठन का विमलु बज चुका है। यदि सरकार नहीं चली, तो प्रदेशभर का किसान सड़कों पर होगा और इस किसान विरोधी निणय को वापस लेने तक संघर्ष जारी रहेगा।

तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से नेत्रहीन दिव्यांग युवक यायाल

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। रामपौली थाना क्षेत्र के ग्राम दोनी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से एक नेत्रहीन दिव्यांग युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना 4 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे की है। घायल युवक सनज डहारे पितृ सुरदासल दहलू 32 वर्ष की उमर के लिए जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया है। प्रत्येक जनकरी के अनुसार सनज बीकाना इंदिरा वंदे का अग्र है तथा नेत्रहीन है। 4 अगस्त को दोपहर 3 बजे सनज गांव के गांधी चौक पर गुड्डा लेते गए थे। गुड्डा खोदने के बाद वह अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान माता मीर के पास सामने से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटने में उसकी कमर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल संचय को उतकर पास को दफन को बीच पर लिखा और उसके परिवजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवजनों के घर पहुंचे और निजी वाहन से उसे जिला अस्पताल बालाघाट ले जाने का काम कर दिया। जहां उसका उपचार जारी है। जिला अस्पताल पुलिस ने घायल का बयान दर्ज कर मामले को अग्रिम कार्रवाई के लिए रामपौली थाना पत्र दिया है। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर का मालिक प्रदीप मोहंते तथा चालक जितेंद्र मोनेश्वर बताया गया है। पुलिस मामले को जांच कर रही है।

आला हजरत का 108 वां सालाना उर्स आज से

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। पूरी दुनिया को इस्लाम धर्म की मूल विचारधारा सुफीवाद की पहचान कराने वाले, विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरु अल्लाह सुफी सैद इमाम अहमद रजा खान आला हजरत के तीन दिवसीय 108 वां सालाना उर्स की शुरुआत आज से 6 अगस्त से होगी। जिसका सल्लाह करीब 8 अगस्त को कूल की फातिमा के साथ होगा।। उस की पूरी अकीलत के साथ पूरे भारत सहित जिले में मनाना जाएगा।लाता हो कि अलले सुफी के मुहल्लाय बरौरी शरीफ से तारीख का ऐलान होने के बाद 6 अगस्त को कूल के गैंग्ड पुरी समरद और काली दुरा परमम कुर्माई के साथ उस कार्यक्रम को शुक्रआरा की जाणगी इसी भाई में बालाघट मुहल्लायधर्म में माना मकिल के अलावा अमर मकिलों और मुहल्लय बाहल्लय क्षेत्र में 8 अगस्त शुक्रआरा को दोपहर 2.38 बजे कूल की विशिष्ट फातिमा के साथ विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम और लंर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।आला हजरत एक पश्कन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष शाही शोएब खान ने बताया कि उर्स के अवसर पर कुरान खानी, मिलाद खानी, दूरद की मरफिल सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश आलाघाट जमा मकिल और शहर की अमर मकिलों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे और आला हजरत की जौनी पर तजरीर दी जाएगी। बलदेन अध्यक्ष शाही शोएब खान ने बताया कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का नाम 1856 को भारत के बरौरी शरीफ में हुआ था। निम्न जन्म के समय भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। अंशज अपने फरैर से कीर्मां को आपस में लडाकर, कमजोर और भीमल करने का काम कर रहे थे। दोलात और शोहरत की खातिर बड़े-बड़े नामचीन, अंशजों के गुणमन बनकर, इस्लाम और कीम के खिलाफ थे। ऐसे वक में आला हजरत ने अपने इल्म और विश्वास के साथ काली की सच्चाई को लोगों के सामने लाकर भरी और स्थापित की। बचपन। उन्होंने भरी और सच्चा विचारों दुस्मन और शहारी को बेनकार कर पूरी दुनिया के इस्लाम अनुयायियों पर एसान किया। इस्लाम की सच्चाई के लिए हुसामुलमुहम्मद, बराया शरीफ, अल लदिल्ल मलकोबी और "फनाया रजिब्य" जैसी लाइव 13 सी अंशज किताबों के अलावा कुआन का अनुवाद कंजुल ईमान के रूप में देकर पूरी दुनिया को अल्लाह और उसके रसूल की पहचान कराते हुए इस्लाम के अमर पंथ शांति के संदेश को सही रूप में साबित किया। श्री खान बताते हैं कि आला हजरत ने 17 दिसंबर 1920 को आला हजरत ए-मुसलमान नाम से संगठन का काम किया गया था। जिसके माध्यम से समाज को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना था। आज जहरत है कि संगठन से जुड़कर हम सामाजिक प्रगति के लिए कार्य करें। इसलिए हम सभी मसलके आला हजरत के मानने वालों को बरौरी शरीफ से जुड़कर काम करने की जरूरत है।

तीन वर्षों में चार लोगों

की हो चुकी है मौत

बेलसिंह परते, नन्दलाल मेरावी,सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान बाघ और अन्य वन्यजीवों के हमलों में चार लोगों की जान जा चुकी है।इसके अलावा दर्जनों भैंसों, पातु कुत्ते, बकरे, बकरियां, बरख और गुरी-गुरीयां भी वन्यजीवों को शिकार बन चुके हैं। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों का बाघ बिखाई देते हैं, जिससे हर दिन जान का खतरा बना रहता है। महिलाओं और बच्चों में भी भय का माहौल है।

खेत जाने में भी डर रहे ग्रामीण

ग्रामीण टेलसिंह,मंगलाल मेरावी,सहित अन्य स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के इस मौसम में खेती का कार्य चमप पर है, लेकिन बाघों की मौजूदगी के कारण किसान खेतों तक जाने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार खेतों और जंगल की सीमा पर बाघ दिखाई देते हैं, जिससे हर दिन जान का खतरा बना रहता है। महिलाओं और बच्चों में भी भय का माहौल है।

मुआवजे में देरी से बढ़ा आक्रोश

पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि वन्यजीव हमलों में जान-माल का नुकसान होने के बावजूद कई महीनों से मुआवजा और सहायता राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि बा-बार आवेदन और अधिकारियों से संपर्क करने के बाद भी केवल आधासठ ही मिल रहे हैं। इससे ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।

सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने की मांग

जनपद पंचायत परसवाड़ा अध्यक्ष सम्मलसिंह धुवं सहित अन्य ग्रामीणों ने वन विभाग और कान्हा प्रबंधन से मांग की है कि प्रभावित गांवों में गश्त बढ़ाई जाए, बाघों की निगरानी के लिए विशेष टीम तैनात की जाए, सवेदनशील लोगों में अलर्ट जारी किया जाए और पीड़ित परिवारों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में और भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं।

अधिकारियों से नही हो सका सम्पर्क

ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों और मुआवजे में देरी के संबंध में फिलहाल वन विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। विभाग की प्रतिक्रिया के बाद ही स्थिति और दावों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। पूरे मामले को लेकर हमने वन विभाग के अधिकारियों के संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

पिछले 3 दिनों से जारी है पटवारी संघ की हड़ताल, राजस्व का काम ढप

5 में से 4 मांगों पर बनी सहमति,प्रांतीय स्तर पर सरकार से बातचीत जारी, वर्षाकाल में आरबीसी प्रकरण, नामांतरण, बंटवारा ठप, किसानों को हो रही परेशानी, कहा-भर्ती पटवारियों के पद पर ही हुए, उसी पद सेवानिवृत्त होंगे ?

पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

वर्षों से लंबीत अपनी विभिन्न पांच सूची मांगों को लेकर बालाघाट सहित प्रदेश भर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।तीन दिनों से जारी उनकी यह हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। जहां पटवारी संघ द्वारा उनको समेत मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई गई है। हालांकि सरकार और पटवारी संघ के प्रतिनिधि मंडल के बीच 5 में से 4 मांगों पर सहमति बन चुकी है,लेकिन पटवारी संघ सभी पांचों मांगों को पूरा करने पर अड़ा हुआ है जिसको लेकर हड़ताल जारी है।आप दिनों की तरह ही बुधवार को जारी इस हड़ताल के दौरान जिला पटवारी संघ के पदाधिवारी तहसील कारलयय के बाहर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते रहे जिनोंने राजस्व के किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाया। जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार से नाराज चल रहे पटवारी,जिले के 600 पटवारी भी हड़ताल पर

सरकार की हर योजना को जमीन तक पहुंचाने वाले पटवारी इन दिनों खुद सरकार से नाराज हैं। आवेदन और निवेदन के बाव भी भिती मानी जाने से बालाघाट जिले के 600 से अधिक पटवारियों ने काम बंद कर दी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। तहसील कारलयय के सामने पंडाल लगाकर सरकार पर बैठे पटवारियों की हड़ताल से न सिर्फ पटवारी कामकाज प्रभावित हो रहा है, बल्कि वर्षाकाल में किसानों और आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कई तरह के कार्य हुए ढप

पटवारियों का इस हड़ताल से नुकसान में सबसे ज्यादा जरूरी, काम ठप पड़ गए हैं। वर्तमान में वर्षाकाल के काम ठप पड़े हैं। इस दौरान संपर्क, तेज बारिश से मकान गिरना या क्षतिग्रस्त होता जैसी आपदाओं में आरबीसी के तहत प्रकरण बनकर पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिलाने की सबसे अहम कार्य पटवारी ही होते हैं। लेकिन हड़ताल के कारण ये प्रकरण



पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। इसके साथ ही नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, सीएम हेल्लान्ड सहित राजस्व से जुड़े सभी जरूरी काम भी ठप पड़े हैं। इससे किसान और आम नागरिक तहसीलों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

हड़ताल से जनता परेशान

पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से जिले की सभी तहसीलों में राजस्व संबंधी काम प्रभावित हो रहे हैं। खेत की नाप-जोख, सीमांकन, भौती नामांतरण, ऋण पुस्तिका जैसे काम करने से किसान परेशान हैं। वहीं आवबीसी के प्रकरण लंबित होने से आदाय प्रभावित परिवारों को समय पर मदद नहीं मिल पा रही है।पटवारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मुद्दा मांग पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस देखा होगा कि सरकार पटवारियों के इस मांग पर कब तक निर्णय लेती है।

5 में से 4 मांगों पर सहमति, मुख्य मांग अटकी

जिल्हास्थ विस्तरवा ने कहा कि हम काम बंद नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ रही है। प्रांतीय मंत्रालय की सरकार से लगातार बातचीत चल रही है।

पांच मांगों में से चार मांगों पर सरकार सहमत हो गई है और उरमें से दो मांगों के आशरा भी जारी हो चुके हैं। लेकिन सबसे प्रमुख मांग समकामन वेतनमान और पदोन्नति को लेकर अब तक कोई ठप निर्णय नहीं हुआ है। इसी कारण हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

पदोन्नति नहीं, इसलिए सड़कों पर उतरे पटवारी

मध्यप्रदेश पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष अरुण बिस्वास्ने ने बताया कि हर विभाग में भर्ती के लिए पदोन्नति को प्रक्रिया होती है, लेकिन पटवारी एकमात्र ऐसा पद है जहां व्यक्ति भर्ती भी पटवारी के पद पर होता है और सेवानिवृत्त भी उसी पद से होता है। जबकि तहसील के खपारी तक प्रमोशन पाकर बाबू और नाबब तहसीलदार तक पहुंच जाते हैं।इसी विसंगति को दूर करने के लिए पटवारी लंबे समय से समकामन वेतनमान की मांग कर रहे हैं। जिल्हाध्यक्ष ने बताया कि पटवारी आरआर और नाबब तहसीलदार के पद पर प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन 2018 के बाद से नाबब तहसीलदार के लिए कोई परीक्षा नहीं हुई है और न ही आरआर के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी वजह से पटवारियों का भविष्य अंधकार में है।

ग्राम बोरी के जंगल झरने से एक व्यक्ति की लाश बरामद

तुकाराम की शराब के नशे में झरने में डुबने से मौत होने की संभावना पद्मेश न्यूज। बालाघाट। ग्रामीण थाना नवगंव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरी के जंगल स्थित एक झरने से एक व्यक्ति की लाश मिलने से सखसी फैल गई। मृतक की पहचान तुकाराम पिता गोपीचंद बागडे 45 वर्ष आयु लिंगा निवासी के नाम से की गई। जिसकी इस बारे में डुबने से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ग्रामीण पुलिस ने इस व्यक्ति का शव पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिवारों को सौंप दिया है और मांग कायम कर जलन शुरू की है। ग्राम जाकारा की अनुसार ग्राम लिंगा निवासी तुकाराम बागडे खेती मजदूर करता था। 3 अगस्त को सुबह तुकाराम घर से जंगल में लकड़ी (ढावा) लेने जाने की बात कहकर निकला था। परिवजनों ने अनुसंधार वह शराब के नशे में था। देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर उसकी रात्रि में ही गांव मोहल्ले आसपास के गांव में खोजबीन की गई किंतु वह नहीं मिला। 4 अगस्त को परिवजनों ने तुकाराम की तलाश शुरू की तलाश के दौरान ग्राम बोरी से करीब तीन किलोमीटर अंदर जंगल में स्थित एक झरने के निकट तुकाराम का शव पड़ा मिला। इसकी सूचना तत्काल नवगंव पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिजवाया और आख्यय्य कार्रवाई शुरू की 5 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे पोस्टमार्टम पुलिस ने जिला अस्पताल में शव पंचनामा कराया।कावाही पश्चात तुकाराम का शव पोस्टमार्टम करने के बाद परिवजनों को सौंप दिया गया। प्रांतीय पुलिस में पुलिस का अनुसंधार है कि तुकाराम झरने में पानी पीने के दौरान नशे की हालत में पैर फिसलने से पानी में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि मृतक के वसांतिक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने धारा 146 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विद्यार्थियों की सुविधा बनी प्राथमिकता, कलेक्टर कुमार

सत्यम के निर्देश पर बुदबुदा- नदीदोला पुल की एप्रोच रोड तैयार

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। वारासिन्धी तहसील के अंतर्गत बुदबुदा और नदीदोला के बीच कसानाला पर निर्माणधीन पुल को एप्रोच रोड नहीं होने से ग्रामीणों, विशेषकर छात्र-छात्राओं को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मामला मालाघाट के माध्यम से सामने आने पर कलेक्टर कुमार सत्यम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए लोक



निर्माण विभाग सेतु संभाग के अधिकारियों को एप्रोच रोड तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुल के दोनों ओर अस्थायी एप्रोच रोड तैयार कर दी है, जिससे विद्यार्थियों का आवागमन सुलु हो गया है।

लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग द्वारा कसानाला पर पुल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन एप्रोच रोड के अभाव में पुल का उपयोग नहीं हो पा रहा था। इससे आसपास के ग्रामीणों के साथ-साथ स्कूल आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

कलेक्टर कुमार सत्यम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सेतु निर्माण के एसडीओ को तत्काल एप्रोच रोड तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों और ग्रामीणों की समस्या का शीघ्र समाधान हो सके। लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग के एसडीओ अर्जुन सिंह सेनोडिया ने बताया कि पुल की एप्रोच रोड का कार्य फिलहाल अर्धवर्क तत्त पूरा किया गया है। वर्तमान में वर्षा ऋतु को देखते हुए स्थायी निर्माण संभव नहीं है। बारिश समाप्त होने के बाद एप्रोच रोड का सीमेंट-कांक्रिट (सीसी) निर्माण कराया जाएगा और इसके बाद पुल की विधिवत सामान्य चालावत के लिए शुरू किया जाएगा।

एसडीओ श्री सेनोडिया ने बताया कि छात्र-छात्राओं को परेशानी को देखते हुए एप्रोच रोड पर मुरम और गिट्टी बिखारकर अस्थायी रूप से आवागमन शुरू कराया गया है, ताकि उन्हें स्कूल आने-जाने में कठिनाई न हो। हालांकि, सुरक्षा की दृष्टि से इस कार्य को पूरा करने का आवागमन फिलहाल प्रतिबंधित रखा गया है। उन्होंने बताया कि पुल निर्माण कर रहे ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि वह एप्रोच रोड को लगातार निगरानी रखे तथा आवश्यकता अनुसार समर-समर पर मुरम और गिट्टी डालकर मार्ग को समतल बनाए रखे, ताकि छात्र-छात्राओं का आवागमन सुरक्षित और सुचारु रूप से जारी रहे।

ग्रामीणों ने कलेक्टर कुमार सत्यम द्वारा मामले में त्वरित संज्ञान लेकर तत्काल राहत दिलाने पर संतोष व्यक्त किया है। अस्थायी एप्रोच रोड बनने से विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है, जबकि स्थायी सीसी एप्रोच रोड बनने के बाद वह पुल क्षेत्र के लोगों के लिए सुगम और सुरक्षित आवागमन का महत्वपूर्ण माध्यम बन जाएगा।

कार्यालय तहसीलदार, तहसील लालबर्बा जिला बालाघाट (म.प्र)

इस्तेहार

रा.प्र.क्र./0010/14-154/2026-27 लालबर्बा,तारीख 28/07/2026

न्यायालय न्याय तहसीलदार कनकी रा.प्र.क्र./0010/14-154/2026-27

मौजा-छोतरा रा.नि.प. कनकी

आवेदक दिनेश पिता पुनाजी पिता पंचव नवासी ग्राम छोरा तहसील लालबर्बा जिला बालाघाट...शपथकर्ता (आवेदक) एतदु द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिनेश पिता पुनाजी पिता पंचव नवासी ग्राम छोरा तहसील लालबर्बा जिला बालाघाट द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मौजा-छोतरा रा.नि.प. कनकी तहसील लालबर्बा, जिला बालाघाट में स्थित आवेदक द्वारा उनके पिता, पुनाजी पिता लक्ष्मण का अनुज्ञा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रारकण 12 अक्टूबर 1969 ग 12 (2) म.प्र. मृत्यु पंजीन 1999 दिनांक 12 (2) प्रावधानों के अंतर्गत उपर्युक्त मृत्यु पत्र का पत्रा 10/05/2010 मृत्यु स्थल ग्राम छोरा अंतर्गत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

माध्यम उपर्युक्त पत्र के संबंध में हितवध पक्षकार को समाचार से अवगत कराया जाता है कि उक्त संबंध में न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत जजवर 07/08/2026 के जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो वह दिनांक 07/08/2026 के पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक/अधिवक्ता सहित उपस्थित होकर इस न्यायालय में दावा आपति पेश कर सकते हैं। निम्न तिथि उपर्युक्त प्रादा आपति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 28/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदसुदा से जारी किया गया है।

तहसीलदार
तहसील लालबर्बा, जिला बालाघाट(म.प्र)

बारबेड वायर (काटेदार तार) एवं चेन लिंक जाली

उचित दाम पर उपलब्ध लघु उद्योग निगम गोपाल से संबद्ध

निर्माणा
तिरुपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टोकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोन:- 07632-243531
मो:- 8989976858/9425139988

न्यूज गैलरी

10 साल बाद कॉलेजों में फिर बजेगा लोकतंत्र का बिगुल, हाईकोर्ट के फैसले से छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ

एनएसयूआई का दावा छात्रों की जीत, अब कॉलेजों में उठेंगे छात्र हितों के मुद्दे, वर्षों से ठप छात्र नेतृत्व को मिलेगा नया मंच



बंद होने के कारण महाविद्यालयों में छात्रों की आवाज पूरी तरह दब गई थी। छात्र अपनी समस्याएं न तो प्रभावी ढंग से कॉलेज प्रबंधन में लाया था और न ही उनके पास कोई निर्वाचित प्रतिनिधि था जो उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके।

इसी मुद्दे को लेकर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष शिवम शर्मा ने स्थानीय सफ़्टवैर हाउस में प्रकर वातां आयोजित की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 के बाद से प्रदेश के कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई। उन्होंने कहा कि कुछ माह पूर्व एनएसयूआई के प्रदेश प्राधिकारी आनंद अग्रसरी ने इस विषय को लेकर न्यायालय की शरण ली थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय ने छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए छात्रसंघ चुनाव करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब उम्मीद है कि प्रदेश के महाविद्यालयों में जल्द ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोजित होंगे। प्रकर वातां में मौजूद एनएसयूआई छात्र नेता प्रवेश नकपूर ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव बंद होने का सबसे बड़ा नुकसान छात्रों को हुआ। वर्षों से कॉलेजों में छात्रों को अपने समस्याएं लांसें रहें, लेकिन उन्हें उठाने वाला कोई निर्वाचित छात्र प्रतिनिधि नहीं था। कॉलेजों में भोजन, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल सुविधाएं, पेयजल, स्वच्छता, परिवहन और अन्य शैक्षणिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई मुद्दे लातार सामने आते रहे, लेकिन छात्र नेतृत्व के अभाव में उनका समाधान प्रभावी तरीके से नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि छात्रसंघ केवल छात्र जीवन का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह नेतृत्व निर्माण की पहली पाठशाला भी है। यहाँ से भविष्य के समाजिक और राजनीतिक नेतृत्व की नींव तैयार होती है। जब कॉलेजों में चुनाव नहीं होता तो छात्रों को नेतृत्व विकसित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सहज महसूस हो नहीं मिलता। इसलिए न्यायालय का यह फैसला केवल चुनाव करने का आदेश नहीं, बल्कि छात्र लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एनएसयूआई प्रदाधिकारियों ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव शुरू होने से कॉलेजों में छात्र हितों के मुद्दे मजबूती से उठेंगे। निर्वाचित छात्र प्रतिनिधि को लेकर प्रशासन के सामने समस्याएं रख सकेंगे और उनके समाधान के लिए जवाबदेही भी वय होगी। इसके अलावा न केवल छात्रों की समस्याओं और छात्रों की भागीदारी भी मजबूत होगी। संसदन ने प्रदेश सरकार और उच्च शैक्षणिक विभाग से मांग की है कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द छात्रसंघ चुनाव की अधिकृतता जारी की जाए, ताकि वर्षों से बंद लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके। एनएसयूआई नेताओं का कहना है कि प्रदेश भर के छात्र इस निर्णय का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब समय आ गया है कि महाविद्यालयों में फिर से छात्र नेतृत्व स्थापित हो तथा छात्र अपने अधिकारों और समस्याओं के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद कर सकें।

कल रात 12 बजे से थम जाएंगे बसों के पहिए

बालाघाट सहित पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन बस हड़ताल का ऐलान

कलेक्ट्रेट में सौंपा झापन; यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें, राष्ट्रीयकरण नीति, टैंडर व्यवस्था और किराया वृद्धि सहित सात मांगों पर अब बस संचालक, 8 अगस्त से त्योहारी सीजन में सार्वजनिक परिवहन होगा प्रभावित



सिटी रिपोर्टर।
प्रदेश न्यूज | बालाघाट।

सरकार द्वारा पूर्व में संचालित की जाने वाली मध्य प्रदेश परिवहन सेवा बंद होने के बाद बालाघाट सहित संपूर्ण प्रदेश में परिवहन की जिम्मेदारी संपाल रह बस ऑपरेटर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। जिन्होंने मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर एसोसिएशन के बैनर चले 7 अगस्त की रात्रि 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किए जाने की चेतावनी दी है। संसदन ने स्पष्ट किया है कि यदि 7 अगस्त की शाम 5 बजे तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती, तो सभी बस संचालक शुरुवार रात्रि 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अपनी इसी मांग को लेकर बुधवार को जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें उन्होंने निश्चित समयसीमा के भीतर मांग पूरी ना होने पर 7 अगस्त की रात 12 बजे से बसों के पहिए जाम कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किए जाने की चेतावनी दी है। ऐसे में यदि ऑपरेटर्स हड़ताल पर चले जाते हैं तो केवल बालाघाट ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश में बसों का संचालन नहीं होगा जिससे त्योहार के सीजन, के अलावा बसों से रोजाना काम पर जाने वाले लोगों के साथ साथ, रोजाना बसों से सफर करने वाले बस यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

बस संचालकों और सरकार के बीच बढ़ा टकराव, वार्ता रद्द

प्रदेश में निजी यात्री बस संचालकों और सरकार के बीच टकराव गरमा गया है। जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन बालाघाट ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी सात सूचीय मांगों का समाधान 7 अगस्त तक नहीं किया गया तो 7 अगस्त की रात 12 बजे से प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन बस हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इस हड़ताल का असर बालाघाट सहित पूरे मध्यप्रदेश में देखने को मिलेगा और त्योहारों के सीजन में लाखों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

राष्ट्रीयकरण नीति का किराया खलक विरोध

बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने ज्ञापन में सरकार की प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण नीति का विरोध करते हुए कहा कि इससे निजी बस संचालकों का व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित होगा। संसदन का कहना है कि सरकार द्वारा विभिन्न मांगों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया निजी परिवहन व्यवसाय के लिए घातक साबित होगी, इसलिए इसे तत्काल वापस लिया जाए।

7 सूत्रीय प्रमुख मांगों पर अड़े बस संचालक

ज्ञापन में बस संचालकों ने 7 प्रमुख मांगें पूरी करने की गुहार लगाई है। इनमें बस मांगों के राष्ट्रीयकरण पर रोक लगाने, टैंडर के माध्यम से परामिट देने को प्रक्रिया समाप्त करने, डीजल एवं महंगाई के अनुपयुक्त यात्री किराए में वृद्धि, नए वाहनों के पंजीयन को अनुमति, 15 वर्ष की आयु सीमा समाप्त करने, परामिट के नवीनीकरण में आ



रही बाधाओं को दूर करने और परिवहन कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग शामिल है। बस संचालकों का कहना है कि इन मांगों को लेकर पहले भी कई बार शासन को ज्ञापन दिए जा चुके हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन

जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि यदि तब समय तक मांगें पूरी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में निजी यात्री बसों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया जाएगा।

त्योहारों के सीजन में बढ़ेगी परेशानी

अगस्त माह में रक्षाबंधन, 15 अगस्त सहित कई प्रमुख त्योहार आने वाले हैं। ऐसे समय यदि बसों का संचालन बंद होता है तो सबसे अधिक परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों, छात्रों, नौकरजीराने लोगों और व्यापारियों को होगी। निजी बसें बंद होना से जिले से बाहर जाने वाले यात्रियों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो सकता है।

प्रशासन पर डाली जिम्मेदारी

एसोसिएशन ने ज्ञापन में स्पष्ट कहा है कि यदि मांगों का समय रहते समाधान नहीं हुआ और बस संचालन बंद करना पड़ा तो उससे उत्पन्न होने वाली वन अतिथिवा एवं परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने वाली वन अतिथिवा शासन-प्रशासन की होगी। बस संचालकों ने सरकार से तत्काल वातां कर समस्या का समाधान निकालने की मांग की है।

सरकार हमारी सुनने को तब तैयार

नहीं, इसलिए कि जा रही हड़ताल- मुकेश चौहान

बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन अध्यक्ष मुकेश चौहान ने बताया कि सरकार बस ऑपरेटर्स की मांगों को सुनने तैयार नहीं है, जिसके कारण बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि वह 7 अगस्त की रात से बसों का संचालन बंद कर देंगे। उन्होंने बताया कि बस ऑपरेटर्स की मांगें हैं कि सरकार 7 जुलाई 2026 में प्रकाशित राजपत्र के माध्यम से बसों का राष्ट्रीयकरण कर बस व्यवसाय को समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा रही है, जो बस मालिकों को समाप्त करना है, जिसे सरकार, बस ऑपरेटर्स के हित में वापस ले। सरकार, टैंडर के माध्यम से बसों की राबंदरी लेने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए सरकार ने 6 जुलाई को टैंडर निकाला है, जिसे सरकार निरस्त करे। 2021 के बाद बस यात्री किराया को संचालन नहीं किया गया है। जबकि डीजल के दामों में वृद्धि हो गई है। जिसका नुकसान, बस ऑपरेटर्स को उठाना पड़ रहा है, हमारे मांग है कि सरकार, यात्री किराया में 2.50 प्रति किलोमीटर की वृद्धि करें तबना वाहनों का पंजीयन करे। 15 साल की बस की आयु सीमा को सरकार खत्म कर फिटनेस रहने तक उसके संचालन को अनुमति जारी करे। सरकार बस ऑपरेटर्स का अंतराज्यीय स्थान परमिटों का नवीनीकरण करें और अस्थायी परमिट स्वीकृति को पूर्ववत निरंतर जारी किए जाए तथा परिवहन कार्यालय में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सुधार किया जाए।

शहर के मेन रोड पर लगा जाम, कुछ देर तक प्रभावित रहा यातायात

मुख्य मार्ग में भारी वाहन के प्रवेश से बिगड़ी व्यवस्था, काली पुलली से हनुमान चौक तक वाहनों की लगी कतार

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। वीते कुछ दिनों से लगातार शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बन रही है, लेकिन इसके बावजूद यातायात व्यवस्था में कोई प्रभावी सुधार नजर नहीं आ रहा। बुधवार 5 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे से 3:30 बजे के बीच काली पुलली से लेकर हनुमान चौक तक मेन रोड पर अचानक लंबा जाम लग गया। करीब आधे घंटे तक वाहन रंगते रहे और दोपहिया, चारहथिया सहित भारी वाहन सड़क पर फंसे रहे। जाम का मुख्य कारण सड़क पर खड़ा एक भारी वाहन बताया जा रहा है, जिसके चलते पूरे मार्ग पर यातायात पूरी तरह अवर-व्यस्त हो गया। घटना का वीडियो और फोटो मने पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वायरल वीडियो में सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें साफ दिखाई दे रही हैं। लोग धीरे-धीरे वाहन निकालने का प्रयास करते रहे, लेकिन काफी होली सड़क और अव्यवस्थित यातायात के कारण स्थिति लंबे समय तक सामान्य नहीं हो सकी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शहर में पिछले कई दिनों से ट्रैफिक जामस्थलता लगातार बिगड़ रही है। प्रमुख चौक-चौराहों और व्यस्त बाजार क्षेत्रों में भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने के कारण आए दिन जाम की समस्या



सामने आ रही है। लोगों का आरोप है कि प्रतिबंधित समय में भी भारी वाहन शहर के मुख्य मार्गों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कुछ ही मिटरों में पूरा यातायात प्रभावित हो जाता है। नागरिकों ने यह भी कहा कि यदि यातायात पुलिस समय-समय पर शहर के सर्वेक्षणशील मार्गों पर गश्त करे और प्रतिबंधित क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती से

कमीन बंटवारे को लेकर छोटे बेटे ने मां और बड़े भाई को डंडे से पीटा जान से मारने की दी धमकी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जमीन के हिस्से के बंटवारे को लेकर हुए विवाद ने अपनी मां और बड़े भाई पर डंडे से हमला कर दिया। घटना में मां बेटे दोनों घायल हो गए। आरोपी ने दोनों को जान से खत्म करने की धमकी भी दी। यह वादना 4 अगस्त को सुबह करीब 8 बजे मलखंड थाना क्षेत्र के गांव कर्मामंडिर में हुई। ग्राम कर्मामंडिर के अनुसूच फूलवती परते 53 वर्ष खेती-किसानी करती हैं। उनके परिवार में पति कलमसिंह रहते हैं। उनके परिवार में एक बेटा और एक बहन हैं। बहन का नाम है। फूलवती अपने पति के साथ अलग रहती हैं। 4 अगस्त को सुबह फूलवती घर पर थीं, इसी दौरान बड़ा बेटा रविन चराने के लिए ले जा रहा था। तभी छोटा बेटा संकत बड़ा पहुंचा और रविन से कहने लगा गुम मां को खेती करती हो, मुझे खेती करनी पड़ेगी। इसी बात को लेकर विवाद हो गया और संकत ने उसने रविन को अस्सील गालियां देना शुरू कर दी। बहन भी फूलवती ने उस गाली देने से रोकती थी संकत अविश्व में आ गया। उसने समय में पड़े डंडे से पहले रविन से मारपीट की। बीच-बचाव करने फूलवती और उनके पति कलमसिंह पर भी उसने डंडे से हमला कर दिया हमराम में फूलवती के गाल पर चोट आई और सूजन हो गई। रविन भी चोटें आईं हैं। मारपीट के बाद संकत ने मुझे खेती नहीं करने पर दोनों को जान से खत्म करने की धमकी दी दी घटना के बाद फूलवती अपने पति कलमसिंह के साथ मलखंड थाना पहुंची। मलखंड पुलिस ने फूलवती की रिपोर्ट पर आरोपी छोटे बेटे संकत पिता कलमसिंह परते के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला कायम कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। निर्माण कार्य के दौरान वैकल्पिक यातायात व्यवस्था नहीं बनाया जाने और भारी वाहनों को डायवर्ट नहीं किए जाने के कारण लोगों को भारी परेशानी उठनी पड़ी थी। अब एक बार फिर शहर के सबसे व्यस्त मेन रोड पर जाम लगने में यह साफ हो गया है कि ट्रैफिक प्रबंधन की समस्या अभी भी उसकी तब बनी हुई है। व्यापारियों और राहगीरों का कहना है कि मेन रोड शहर की सबसे व्यस्त सड़क है, जहां दिनभर हजारों लोगों का आवागमन रहता है। ऐसे में यदि यहां कुछ मिटरों के लिए भी भारी वाहन सड़क पर रुक जाता है तो पूरा यातायात प्रभावित हो जाता है। इसके बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कोई स्थायी प्नीनीति नजर नहीं आ रही। स्थानीय लोगों में जिला प्रशासन और यातायात विभाग से मांग की है कि शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश के लिए समय निर्धारित किया जाए, तो-पार्किंग नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और व्यस्त मार्गों पर अतिरिक्त यातायात पुलिस की तैनाती की जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते दोस कदम नहीं उठाए जाए तो जाने वाले दिनों में शहर में जाम की समस्या और गंभीर रूप ले सकती है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को ही भुगतान पड़ेगा।

मोटरसाइकिल रोड किनारे फिल्लर से टकराने से गंभीर युवक की मौत

डोरा से परसवाड़ा रोड पर हुई थी सड़क दुर्घटना, दो युवक हुए थे घायल

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। रूपर धर्नातल ग्राम डोरा से परसवाड़ा रोड पर मोटरसाइकिल रोड किनारे फिल्लर से टकराने से गंभीर रूप से घायल युवक उमेश पिता दशन लाल ग्वारे 38 वर्ष की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस दुर्घटना में अन्य घायल युवक देवेश पिता भीममल शरणागत 29 वर्ष का इलाज बालाघाट नगर की निजी अस्पताल में चल रहा है। दोनों युवक धाना परसवाड़ा के ग्राम पोणगडोशी निवासी हैं। ग्राम जाकारा के अनुवार 4 अगस्त को उमेश और देवेश मोटरसाइकिल में अपने घर से उक्का काम की तलाश में निकले थे। उक्का में ही उमेश का ससुराल भी है। मोटरसाइकिल देवेश चला रहा था। देवेश को उसके परिवार के लोग नगर के प्राइवेट अस्पताल में ले गए वही उमेश का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा था। रात्रि 11:00 बजे जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उमेश की मौत हो

गई। 5 अगस्त को जिला अस्पताल पुलिस ने शव पंचनामा कार्यवाही के बाद उमेश का शव पोस्टमार्टम करवा कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। और धारा 194 भारतीय



नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मां कायम कर इस मामले को आगे की जांच कारवाही हेतु घटना स्थल से संबंधित पुलिस धाना रूपर भिजवा दी है।

बैगाटोला में एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले के चांटीटोला धाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पारीरौज के बैगाटोला में एक व्यक्ति ने अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 5 अगस्त की रात 5:30 बजे यह घटना उस समय हुई जब व्यक्ति, बहन के अपने बड़े पिता के घर जाने के महज 5 मिटर के अंतराल में अपने घर के अंदर फांसी में झूल गया। चांटीटोला पुलिस में मुक्त संचय पिता वय, जादीरा शरणागत 32 वर्ष का शव अपने कक्ष में लटक मौक की कारवाही की है। ग्राम जाकारा के अनुवार संजय शरणागत खेती किसानी करता था। जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। परिवार में पत्नी दो बच्चे और माँ है। संजय माता-पिता का इस्तीला बेटा था जिसको एक बहन वंदना हरिनखंडे ग्राम बटवा में रहती है। संजय शराय पीने का आदी था और वह आए दिन शराब पीते थे जिससे 15 दिन पहले या बहुत दिन पहले ही संजय की पत्नी दो बच्चों को लेकर अपने मायके गंगपुर चली गई है। संजय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी जिससे 15 दिन पहले या संजय ने पत्नी में यूथिया खाद का सेवन कर लिया था। जिसे बालाघाट नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया और वय्यथ होने पर उसे घर ला लिया गया था। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद वह शराब पीते रहा था। बहन वंदना आकर उसका इलाज करवाती थी। 5 अगस्त को वंदना हरिनखंडे अपने भाई संजय का इलाज करने के हेतु बैगाटोला आई थी। शाम 5:30 बजे करीब जम वंदना हरिनखंडे अपने बड़े पिता के घर चाय पीने गईं थी। वंदना को लंबा वय्यथ आया और वह घर के अंदर चली गईं वही पहुंची उसका भाई संजय घर के अंदर यानी में गमछा बांधकर फांसी पर लटका हुआ था और झटपट आ रहा था। वंदना के निम्नाने पर मोहले पहुंची के लोग दौड़े और गमछा काट कर नीचे उतार तब तक संजय की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर चांटीटोला पुलिस ने बैगा टोला पहुंचकर मृतक संजय का शव अपने कब्जे में लेकर प्रारंभिक कार्रवाई की कि वह का पोस्टमार्टम 6 अगस्त को किया जाएगा।

गड्डों का जल भरमाकर कपड़ों परथान - मोहन

है। महेंद्र दत्तजी ने बताया कि लानचरों से बालाघाट हाईवामा पंगा लानकी मोड़ से जल और मांसां जाती है और इस स्थान पर सड़क के किनारे पट्टी में जहाज-जहाज गड्डे बना रहे हैं जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाए और कपड़ों से उतने गड्डे दिखाई नहीं देते हैं और इसी पानी पर औरपरत कालेजिन र्पिष्ट है, जहाँ से बड़ी सड़क में खोल-छावोल प्रतितिन साकिलल और मोटरसाइकिल से आवागमन होता है। इसके अलावा एक अन्य स्थल तिरहा गाम है जहाँ से एक सड़क लानचरों, दुसरी मोहाना-धरंग और तीसरी सीसे बालाघाट-वासिनीवामा पंगा की ओर जाती है। साथ ही मोड़ मोड़ होने से सामने से आने वाला जहाज दिखाई नहीं देता। जिसके कारण हर समय बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बन रही है और पूर्व में हादसे भी हो चुके हैं। डॉ. दत्तजी ने बताया कि इस स्थान पर मोड़ पर सड़क के जल पर निरवलोकन हो के सड़क डेकर नहीं बनाये गये हैं जिसके कारण दुर्घटनाएँ भी होती हैं। इसलिए शासन-प्रधानन से मांग है कि पट्टी किनारे गड्डों का जल भरमाकर पंगे पंगे मोड़ वाला स्थान पर सीसे डेकर और आवकयुक्त सुरक्षा संकेतन जहाँ जाये तबक आगामन में हो रही संशयनिवृत्ति से निजात मिल सके।

कॉलेज चौक से सिकंदरा चौक बना एकसीडेंट जोन कीचड़ और गहरे कटे साइड शोल्डर से राहगीर परेशान



पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। नगर के बाईं नंबर एक स्थित कॉलेज चौक से सिकंदरा चौक तक का पट्टेच मार्ग खराब हो गया है। सड़क किनारे उभरे जगह जगह छोटे बड़े गड्ढे और उखड़े हुए साइड शोल्डर हर वक्त बड़ी दुर्घटनाओं की न्योता दे रहे हैं। इस मार्ग से रोजाना गुजरने वाले हजारों राहगीर ग्रामीण और स्कूली छात्र-छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं।

तीन प्रमुख मार्गों को जोड़ता है यह व्यस्त चौराहा
कॉलेज चौक से सिकंदरा चौक जाने वाला

यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिकंदरा चौक से एक रास्ता कोरा तथा दूसरा मार्ग थानेगांव की ओर जाता है। इस कारण दर्जनों क्षेत्र के ग्रामीण दैनिक कार्यों, इलाज और व्यापार के सिलसिले में रोजाना इसी रास्ते से वारासिवनी नगर मुख्यालय पहुंचते हैं। इसके अलावा मालवाहक वाहन और यात्री बसें भी लगातार इसी मार्ग से गुजरती हैं। सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि एक तरफ का पूरा साइड शोल्डर कटकर नीचे धँस गया है तो दूसरी तरफ गड्ढों में कीचड़ फैला है। यह पूरा दर्जिन पॉइंट पर है सामने से आचानक भारी वाहन आ जाने पर जब रोपिण्डा चालक अपने वाहन को सड़क से नीचे उतारते हैं, तो गहरे गड्ढों और

धँसे हुए शोल्डर के कारण वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। महाविद्यालय और आवासपास के स्कूलों में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र-छात्राएं रोज इसी मार्ग से आवागमन करते हैं, जो अक्सर इन गड्ढों के कारण गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने इस विकराल होती समस्या से संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और विभाग को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक सुधार का कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। नगरवासियों और राहगीरों ने प्रशासन व संबंधित विभाग से मांग की है कि किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार किए बिना सिकंदरा चौक से कॉलेज गेट तक की सड़क के साइड शोल्डर को

दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों का आवागमन सुरक्षित हो सके।

कालेज चौक पर सड़क की हालत जर्जर से विद्यार्थियों में आक्रोश-शुभम शर्मा

बाईवारी शुभम शर्मा ने बताया कि यहां सड़क किनारे स्थिति बहुत ज्यादा खराब है दर्जिन है पास में महाविद्यालय है और इस स्थिति को देखते हुए सुधार कार्य अभी तक नहीं किया गया है। यहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक का आना जाना होता है सुबह ९ बजे से रोड में भीड़ लग जाती है नौकर पेशा स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी मजदूर

कामगार सभी लोग यहां से आना जाना करते हैं। क्योंकि इधर आगे एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है जहां से हजारों लोग हो जाते हैं। हम रोजाना यहां देखते हैं एकसीडेंट किस प्रकार से हो रहे हैं हमारा घर दुकान सब यही है। यह जो सड़क का शोल्डर कट गया है उसे बहुत समस्या है रोड भी बराबर से नहीं है इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

कॉलेज चौक तक सकारा मार्ग होने से बहुत ज्यादा भीड़ रहती है-नामदेव बैस
ग्रामीण नामदेव बैस ने बताया कि कोरासे और थानेगांव दोनों मार्ग से लोगों का आना

जाना लगा रहता है। ऐसे में कॉलेज चौक तक सकारा मार्ग होने से बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। क्योंकि इधर कोई नगर मुख्यालय जाता है इस दौरान कई बार एकसीडेंट होते हैं हमारे द्वारा उन्हें उठाया जाता है। यह रोड बनी तो इसमें प्रॉपर शोल्डर नहीं भरे गए हैं रोड कट रही है सड़क की स्पष्ट बीट दिखाई देती है जहां से गाड़ी अधिकतर स्लॉप होती है। भारी वाहन के आने पर छोटी गाड़ियां नीचे उतरती हैं वह इस बीट में फंसने से गिर जाती हैं। यहां पर साइड शोल्डर भरने चाहिए व्यवस्था संबंधित लोगों के द्वारा जो जानी चाहिए अन्यथा किसी दिन बड़ा हादसा घटित होने देर नहीं लगेगी।

बिठोड़ी और डोके के मध्य बनने वाले पुलिया का विधायक पटेल ने किया निरीक्षण

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिठोड़ी और डोके के मध्य लगभग ३० लाख रुपये की लागत से नवीन पुलिया का निर्माण किया गया है। मगर पुलिया का निर्माण करने के बाद डेकेदार पुलिया के दोनों ओर एग्रोज सड़क बनाना बहुत गया। जिससे बारिश के समय स्कूल के छात्र-छात्राएं और ग्रामीणजन हादसे का शिकार हो रहे हैं। जिससे ग्रामीणजनों में

बिसेन,यादीवार बिसेन, राजेश पटेल,दुलीचंद पटेल, उमेश पटेल,तिशक पटेल,शत्रुघ्न पटेल,राजकुमार चौधरी,संदेश बिसेन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ग्राम बिठोड़ी के पूर्व सरपंच तेजराज नागपुर ने कहा कि डेकेदार ने जब से पुलिया का कार्य प्रारंभ किया गया था। सभी से उसका काम ना हो समय सीमा के पूर्ण किया गया बारिश के पूर्व उसे कई बार ग्रामीणजन हादसे का शिकार हो रहे हैं। जिससे ग्रामीणजनों में



भारी आक्रोश व्याप्त है डेकेदार को ग्रामीणों द्वारा एग्रोज सड़क बनवाने के लिए बार-बार निर्देशित किया गया। मगर डेकेदार इसे अनदेखी ही करता रहा जिसके बाद विधायक पटेल ने ग्रामीणों,डेकेदार और संबंधित अधिकारियों के साथ मीक पर पहुंचकर निरीक्षण किया और डेकेदार को जमकर फटकार लगाते हुए जल्द दोनों ओर एग्रोज सड़क बनवाने के निर्देश दिए। इस दौरान वन इंजीनियर किरण गर्जभार, सरपंच खुमैंद्र मझुवा,खुपचंद

उसे किसी भी ग्रामीणजन की बातों को नहीं सुना। अभी बारिश का समय है यहां से स्कूलों के बच्चों के साथ ही वाहन का आवागमन होता है और रोज कीचड़ में वाहन फं स रहे हैं। हमने विधायक और संबंधित अधिकारियों को मीक पर बुलवाकर चेतावनी दी है कि अगर १५ दिनों के भीतर एग्रोज सड़क नहीं बनवाई जाती तो ग्रामीणों द्वारा डेकेदार के निरुद्ध आंदोलन किया जाएगा जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन को होगी। वहां विधायक पटेल ने कहा कि विधायक बनने के बाद हमारे द्वारा लगातार संबंधित मांत्रियों और अधिकारियों से मूलकात कर ग्राम पंचायत बिठोड़ी से डोके के मध्य नवीन पुलिया स्वीकृत हुआ



पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगरगांव की नहर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने पानी में एक अज्ञात युवती का शव बहावा हुआ देखा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से शव को बाहर निकाला गया। मृतिका के गले पर धारदार हथियार से रेतने का गहरा निशान पाया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया यह मामला जघन्य हत्या का प्रतीत हो रहा है।

खेती किसानों के दौरान ग्रामीणों की पड़ी नजर
प्रास जानकारी के अनुसार वर्तमान में खेती किसानों का कार्य चल रहा है जिसके लिए नहर में पानी भी छोड़ दिया गया है। वहीं रोजाना किसान अपने खेती-बाड़ी के कार्यों से आना जाना कर रहे हैं,ऐसे ही मंगेश्वरी से डोंगरगांव बूढ़ी नहर किनारे किसान अपने कार्य के लिए गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा की नहर में एक काले कपड़े में कोई व्यक्ति का शव बहावा हुआ जा रहा है। यह देख ग्रामीणों के द्वारा तत्काल नहर का सुरक्षा स्थान देखकर पुलिस के पास नहर में उतरकर बड़ी मशकत के साथ शव को



युवती का शव मिलने पर शिनाख्त की कार्यवाही जारी रखी गई। तभी शिनाख्त की कोशिशों के बाद किसी व्यक्ति के द्वारा मृतिका की पहचान खुशबू डहरवाल पिता शंकर डहरवाल उम्र २४ वर्ष के रूप में हुई। खुशबू का प्ल परिवार ग्राम खमरिया बाना लालरस का रहने वाला है। लेकिन वर्तमान में उसका परिवार नागपुर में शिफ्ट हो चुका था। खुशबू वहां अपनी मां और भाई बहन के साथ रह रही थी। खमरिया में उसके चाचा चाची निवास करते हैं। इसमें बताया जा रहा है की खुशबू बीते ३१ जुलाई को बिना बताए घर से कहीं निकल गई थी जिसकी गुमशुगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। खमरिया में रहने वाले उसके चाचा चाची के घर भी वह नहीं पहुंची थी।

५ घंटे की मशकत के बाद पीएम के लिए भेजा गया शव
फोटो के माध्यम से शिनाख्त की पुष्टि होने के बाद पुलिस प्रशासन ने करीब ५ घंटे तक चली प्रारंभिक जांच प्रक्रिया पूरी की। इसके पश्चात शव को सुरक्षित रूप से सिविल अस्पताल वारासिवनी के पोस्टमार्टम गृह में रखा दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम ६ अगस्त की सुबह किया जाएगा। युवती का

अचानक लापता होना और फिर गर्दन पर धारदार हथियार के निशान के साथ नहर में शव मिलना, हत्या की ओर सीधा इशारा कर रहा है। पुलिस ने पूरे मामले में हत्या का अंदेशा जाता हुआ बारीकी से विवेचना और जांच शुरू कर दी है।

मामले में आवश्यक कार्यवाही कर जांच की जा रही है-अभिषेक चौधरी
एसडीओपी अभिषेक चौधरी ने बताया कि डोंगरगांव की बूढ़ी नहर में एक युवती का शव बहावा हुआ बताया किया गया था। युवती पर पुलिस के द्वारा मीक पर आवश्यक कार्यवाही की गई और संवेदनशील मामला होने के कारण मीक पर में व वारासिवनी लालरस थाना प्रभारी पहुंचे थे। एफएसएल एवं फोटो के माध्यम से शिनाख्त की पुष्टि होने के बाद पुलिस प्रशासन ने करीब ५ घंटे तक चली प्रारंभिक जांच प्रक्रिया पूरी की। इसके पश्चात शव को सुरक्षित रूप से सिविल अस्पताल वारासिवनी के पोस्टमार्टम गृह में रखा दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम ६ अगस्त की सुबह किया जाएगा। युवती का

चावल घोटाले में एफसीआई कर्मचारी सुर्दे सूर्यवंशी और संचेती राइस मिल का अकाउंटेंट जेल दाखिल

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। करोड़ों रुपये के बहुचर्चित सरकारी चावल घोटाला मामले में एसआईटी और पुलिस के कार्यवाही लगातार जारी है। रिमांड अवधि समाप्त पर पुलिस ने एक सीआईड के सहायक गेड,१ कर्मचारी गोदान सहयक सेल प्रभारी सुर्दे सूर्यवंशी और संचेती राइस मिल के अकाउंटेंट को ५ आगस्त को वारासिवनी न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां से न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक कुल १७ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि अन्य स्तर आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। एसआईटी ने पाया की सरकारी आगार सुरक्षा की जिम्मेदारी संचालने वाले अधिकारी इस नेवर्क में भी शामिल हैं। कर्मचारी सुर्दे सूर्यवंशी पर आरोप है कि वह राइस मिलर्स और दलालों के बीच निःशर्तक नक्कल काम कर रहा था।

अभी तक यह आरोपी हुए गिरफ्तार
इस चावल घोटाले के मामले में अब तक जांच में पकड़े एफसीआई ऑफिसर प्रहलद के प्रतिनिधि रहल

प्रताप, सुपरवाइजर राकेश श्रीवास्तव, टुक चालक दुर्गाश शंडे, टुंगसंपूर्ण डेवरे बाना, राइस मिल संचालक कुंजीबहादुर पटेल, मुनीम अतुल बिसेन, सुर्दे गण, गोविंद माहेश्वरी,जुगलकिशोर खडेलवाल, किशनलाल खडेलवाल, राजेश संचेती, विनोद शर्मा, गोपाल ठाकुर, अविनाश कावरे, सोनू जैन, सुर्दे सूर्यवंशी और संचेती राइस मिल का मुनीम शमाल हैं।

जांच जारी अन्य फार आरोपियों की तलाश तेज
एसआईटी के द्वारा इन जांच में गिरफ्तार आरोपियों के पास से जघन दस्तावेजों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। मामले से जुड़े अन्य सल्लित और फार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ताकि इस घोटाले की पूरी कड़ी को बेनकाब किया जा सके इस कांशिश में पुलिस टीम पूरी तरह लगी हुई है।

श्रीराम नगर गायखुरी में आयोजित श्री शिव महापुराण सम्पन्न
यज्ञ हवन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दी आहुति, वितरित किया भंडारा



भगत में आगत से नवम्ब तक सम्पन्न आगत और त्योहारों का मीसम नामा जाता है। रक्षाधरणी, वज्राधरणी, गणेशोत्सव, नवरात्र, दशरहा, दीपावली और छठ जैसे पर्वों के दीन जकार में पर्वधारि अपने पर्व कर रहती है। यही वह सम्पन्न होला है जन् पर्वधारि बहो, भेरु, सामना, लेखनिकी, उजवा, वाजना, मिडगुली और दैनिक उजगम की वक्तुओं की खरीद अधिक करते हैं। लेकिन इस वाजना त्योहार मीसम खुले से भरे होला है मोगाई का दवावा बन्दे के सम्पन्न भिसे रहे हैं। कच्चे मात और ऊर्जा की ललाम में पर्व के कारण कछ प्रखु उभोपाका कर्णियां अपने उजवा की कर्णियां में बहोती करे की तैयारी कर रहती हैं। यदि सिस होला हो तो इसका सिसा असर आत कर्णियां के मासिक बजट और त्योहार खर्च पर पड़ता। उद्योग जगत और होला से भिसे सम्पन्न बाला हैं कि डिट्टर, सागु, दूधरस, पैकबन्दे खाद्य पदार्थ, छाछ होला, चर, दियर, अलियर, पेर, भेरु उजगम, उभोपाका इहोवनीकियां और कुछ अउर उजवा के दियम चरकनदर कोसे से बहवा जग सम्पन्न हैं। कछ कर्णियां यहाँ से अपने उजवा की कर्णियां में सीमित करे कर चुकी हैं। जबकि कुछ कर्णियां अपने बाले हाथों में यह मूल्य खुसी लाता करे की योजन बा-

फजी खबरों और डीपफेक का बढ़ता खतरा

[illegible][illegible]

कि यापनी सत्यपन के प्रमाति किजा जात है। इसका देखिये यावन्तीका लज्जा, अधिक लज्जा, सामाजिक तनाव, वैवाहिक प्रश्न या अधिक विव्कल और दुर्लभ प्रश्न हो कर सकता है। इसके विपरित डीपेकक बुद्धिमता को सहस्रता से तीव्र या परिवर्तित स्वस्थ, आरामय यावन्तीकी है, जिसमें किसी व्यक्ति को जेना प्रतिपादित करे या सत्य बचक देवे होइ दिखाना जात है। यावन्तीका नहीं होता। लिखित जावन्ती या यावन्ती संदेश कर जाती है, लेकिन जब वही सुनाती किसी परिवर्तित चेहरे और यावन्तीक लज्जे वाली अवस्था के साथ प्रसूत हो, तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं अधिक हो सकता है (निरुपेक)। डीपेकक को ज्ञात और सत्य को केवल के संकेत से ज्ञात है। सम्पत्ति केवल नतीजे सामाजी को पचावन करती है। वही नहीं है। बल्कि ऐसा डीपेकक बुद्धि में प्रमाण, स्त और विव्कलता को रक्षा करने में है, जहां बुद्धि बुद्धिमता यावन्तीका उत्तरी सामाजी कर कर सकती है। साध्याँ, डीपेकक का समर्थ कर खड़ा यह नहीं कि लोग केवल नकली वीडियो को सम जानते हैं। इसमें ही लोग स्थिति तब उभर जाते हैं, जो पीछे यावन्तीका वीडियो और वास्तविक प्रमाणों को ही डीपेकक वास्तव अर्थवाक्य करे लगे। यदि किसी व्यक्ति का यावन्तीका वीडियो समने आए, तो वह यह दावा कर सकता है कि उसे (आईड) द्वारा बनाया या परिवर्तित किजा गया है। इस स्थिति को लार्सन डिपेडिड का ज्ञाता है, अर्थात् तकनीक का ऐसा लाभ, जो कुछ वीडियो देवे कि यावन्तीका प्रमाणों से बचने का अवसर दे सकता है। परिणामस्वरूप सामाजी में एक ही पुरी तरह सम नहीं है। ऐसे नागरिकाता विव्कल हो सकती है। संकेतित केवल मतदान को प्रक्रिया से लोकांत नहीं होता; वह साक्षा अर्थ्यों, विव्कलपय सुचना और विव्कल विधास पर ही आधारित होता है। यदि सम को पचावन हो विवाहित हो जाए, तो यावन्तीका संवाद और जमन दोनो कमजोर पड़ सकते हैं। साध्याँ, चुनौती और राजनीतिक व्यवस्था पर डीपेकक का प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हो सकता है। किसी चुनाव से कुछ देर पहले वीडियो ऑनलाइन होता है जो नकली वीडियो प्रमाति किजा जाए, जिसमें वह

[illegible]

प्राचीन वैद्य और रसायनज्ञक उपयोग के प्रतिपात आती है और कौन-सी दवायों, मूलद्रव्यक ढोखा, आर्थिक नुकसान, हिंसा, मानववृक्ष हल्लेख या प्रतिका के लानि पहुँचाने के लिये, बनाई गई है। एसाई यन्त्र साम्य नहीं है; उसका अनेकत और हाँकारक उपयोग मरम्या है। साधियों प्रकृतिगत जगत को भी उस तकनीकी को भी आरामयन्त्र कहना उचित होना ।

एसाई यन्त्र व्यापारगत के व्यापारियों वरिष्ठ हल्लेख प्रथमप्रायः द्वारा प्रकृतिगत के नाम पर मोबाइल और माइक के अनियोजित उपयोग तथा लोगों को डराने-धमकाने के अर्थव्यथित टिप्पणों का व्यापक अर्थ है। प्रसंग की वजहसे लातेविक के लिये अनिवार्य है, प्रकृतिगत प्रकृतिगत की आश्रम में भग्न पदा करना, मानव सन्धान आरोग्य लाक्षण, निजी प्रतिका के प्रकृत पदधान या कानुन-व्यवस्था को प्रभावित करना स्वतंत्र प्रकृतिगत नहीं कहा जा सकता। मोबाइल कैमरे ने नागरिक प्रकृतिगत की शक्ति दी है, जिसे किङ्क साध समुपेक्षणी की शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति को समुपेक्षणी और माइक के सहित सार्वजनिक समुपेक्षणी साहस है, वह स्वतः प्रकृतिगत के प्रकृतिक मानदों को पालन नहीं कर रहा होना ।

प्रकृतिगत की पदधान केवल उपयोग के नहीं, बल्कि सन्धान, निष्पक्षता, जनहित, उत्तरदायित्व और नैतिक आचरण से होती है।

साधियों, एसाई युग में प्रकृतिगत का महत्व कम नहीं, बल्कि अतिरिक्त बढ गया है, यथा सोलार मोडिया पर सूचना को बाढ़ होना, तब विश्वसनीय प्रकृतिगत सन्धान, प्रतिका और प्रमाण उपलब्ध करता है।

मानवस्य सन्धानों को तस्वीरों और वक्ताओं के बोले, स्वयं, स्थान और तकनीकी सामाजिकता की जाँच करनी चाहिए। एसाई आधारित तथ्य-जोड़क उपकरणों का उपयोग अत्यधिक है, लेकिन अतिम संपादकीय प्रविष्टिगत मानव प्रकृतिगत और अनुपेक्षणीत संपादकों के हाथ में आता चाहिए।

चूनातै

उजार-चूवड़ को प्रेमिय कवलय पूतल और डीजल तेल सीमिय नूतल बालक पालरिख, फैसियन, सामान उडोग और परिवहन व्यवस्था पर प भइतल है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा महंगे होने का शर और थिर-थिर चलेल बाजार में रोजगार को वस्तुओं तक पहुंच-ग सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहती है। कंपनियां भी इस अवधि में, यदि वे लालत बंदूक के बाजुख उभोका खोदत और खरदो तो दो कंपनियों में अपेक्षाकृत आसानी हो सकती है। उद्योग घर का मानना है कि नवतुलन मूल को हलिस ग्राहकों तक पहुंचाना जा सकता है। हालांकि कंपनियां यह भी बाद उभोकाओं की खोदत पर किस्मत परमापन करेगी है। यदि मूल समजोरो की गति धीमी हो सकती है। हाल के महीनों में प्रमोशन और शहरी दोनों क्षेत्रों में मूलें हूँ है। बहुरी विक्री के अलावा भी बाजार में सकारात्मक स्थितियों पर कंपनियों को विस्वास है कि योशोरी सड़क में विक्री अधिक रहेगी।

का पूरा बोझ स्वयं
कर ऊर्जा की बढ़ती
सामग्री, धातुओं,
से उत्पादन लागत
से कंपनियों की
है तो कंपनियों
में लंबे समय से
तेल की कीमतों में

ई-20 के बहाने राजनीतिक टकराव-
प्रधानमंत्री आवास मार्च, विरोध की राजनीति
और चुनावी माहौल में बढ़ती सियासी गर्माहट
-कवितालाल मांजरेत

हिंदी की राजनीति एक बार फिर उस समय गरमा गई जब कांग्रेस के अंदर पार्टी के शीर्षों संयोजक एवं हिंदी के पूर्व मुख्यमंत्री आरविंद केजरीवाल ने ई-20 15-16 नयी नीति के विरुद्ध भी प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने का प्रयास किया। हिंदी पुलिस से सुरक्षा कार्रवाई और वाद प्रविर्भावों का हवाला देते हुए उन्हें प्रतिरोधशाली राह पर रोके दिया। इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिंघाविया, संजय शर्मा, जैमिन शाह और अन्य नेताओं ने वहीं प्रयास शुरू कर दिया। इस आंदोलन में पार्टी का कहना है कि उनसे देशभक्त से दोला सते हैं, अधिक लोगों को ओर से लिखी गई चिट्ठियाँ और याचिकाएँ प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का प्रयास किया, जबकि पुलिस ने उन्हें अयोग्य बंदे को अनुमति नहीं दी। बाद में पार्टी नेताओं ने वादा किया कि वे जो आपन पुलिस अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेज दिए गए।

आम आंदामी पार्टी का आरोप है कि १८० नौति आम उपभोक्ताओं और वाहन मालिकों के हित में नहीं है। पार्टी का कहनाय है कि इस ईधन के व्यापक उपयोग से लाखों वाहनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है और सरकार को लोगों के हित सामान्य पेट्रोल की भांति २० टोनों विलयत उपलब्ध कराने चाहिए। केजरीवाल ने भी आरोप लगाया कि सरकार बाहरी दबाव में निर्णय ले रही है। हालांकि ईंधन की कीमतों को और से पहले भी यह कहा जाता रहा है कि एनोली मिश्रित ईंधन का उद्देश्य तेल के अभाव पर निर्भरता कम करना, प्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाने में सहायता करना है। इस प्रकार दोनों पक्ष इस मुद्दे को अलग-अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम का इसूरा महत्वपूर्ण चर प्रदर्शन का अनुभव है। इसी सूखा व्यवस्था है। प्रधानमंत्री आवास के आवासप का क्षेत्र में उच्च सूखा वाला माना जाता है, जहां बिना अनुमति किसी प्रकार के परिवर्तन या जुनूस का इजाजत सामान्यतः नहीं दी जाता। महाराष्ट्र की नगरपालिका सूखा संज्ञाओं का संबंध भारतीय के महाराष्ट्र में विशेष रूप से लागू रहती है। ऐसे में पुलिस द्वारा मार्च को रोकेना सूखे, विशेषज्ञों का हिस्सा बनाया गया। इसी ओर आगे सूखा का कठना है कि लोकेशन में जनता को आवास सरकात तक पहुंचाने का अधिकार सभी को है और शांतिपूर्ण विरोध को इस प्रकार रोकना जनता उचित नहीं है। वहीं विरोधभास भारतीय लोकेशन में अक्सर सड़क बंद करने को मिलाता है, जहां सूखा और लोकालीक अधिकारों के बीच सतून बना रहता है। सूखा की चर्चाती नहीं रहती है।

राजीनीति का इष्टि से देखा जाता तो इस प्रश्न का समर्थन सभी मूल्यपूर्ण माना जा चुका है। देश के कई राज्यों को चुनने के मुद्दे को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी (हिंदू) और पंजाब से बाहर आने राजनीति विस्तार को कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे पर मुख्य होकर वह स्वयं को विपक्ष के प्रमुख आवाज के रूप में स्थापित करना चाहती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि इस प्रकार जटिल से अधिक राजनीति का उद्देश्य से प्रेरित है और इसका प्रकट चुनावी माहौल में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भाषा नेताओं ने इसे आज़म राजनीति का प्रमाण देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर धनानुरोधी आवाज को और भाषा आधारित केवल उधारवी देने करने को कोशिश है।

यह भी उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी लगातार विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति अपनाती रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी और अब ई-20 नीति वही कारणों को लेकर पार्टी आंदोलन करती रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि विश्व अपनी राज्य सरकारों की चुनौतियों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे आंदोलन करता है। पंजाब में कानून-व्यवस्था में भारी समस्या और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला जोरोंती रही है। विश्वीय दल के बीच यह आरोप-प्रत्यारोप भारतीय राजनीति का सामान्य हिस्सा बन चुका है।

इस पूरे घटनाक्रम में सोशल मीडिया और नए राजनीतिक समूहों को संकलता भी चर्चा का विषय बनो हुई है। हाल के समय में नए संगठन और पारंपरिक सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से लोकप्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न दल एक-दूसरे पर आलोचनाओं को समर्पित देने या उनसे प्रेरित होने के आरोप भी लगाते हैं। हालांकि ऐसे दावों के संबंध में ठोस प्रमाण सामने आने पर ही किसी विषयक पर पड़ना उचित होगा। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक संगठन या पड़ना का मूल्योक्त होने से विचारों, कार्य और कारणाति स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए।

ई-20 नीति के अन्तर्गत एक ऐसा विषय है जिस पर राजनीतिक आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से गंभीर चर्चा का आवश्यकता है। यदि कुछ वाहन मालिकों को तकनीकी और आर्थिक चिंताएँ हैं तो सरकार, विशेषज्ञों और वाहन निर्माताओं के बीच संवाद होना चाहिए। इसी प्रकार यदि सरकार इस नीति को देश के दीर्घकालिक हितों में मानी है तो उसे पारदर्शिता के साथ उसके लाभ, संभावित चुनौतियों और समाधान के बारे में जनता को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। किसी भी सार्वजनिक नीति को सफलता के कवल सरकार से नहीं बल्कि जनता के विश्वास और सहभागिता से तय होती है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन एक संस्थापन अधिकार है, लेकिन उसके साथ कानून और सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन भी उतना ही आवश्यक है। राजनीतिक दलों का जिम्मेदारी केवल विरोध करना नहीं बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी है। दूसरी ओर सरकार का जिम्मेदारी है कि वह जनता की चिंताओं को गंभीरता से सुने और संवाद का रास्ता खुला रखे। जब संवाद की जगह टकराव बढ़ता है तो राजनीतिक ध्व्यकरण और अविश्वास भी बढ़ता है।

आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ई-20 नीति को लेकर सरकार और विश्व के बीच संवाद स्थापित होता है। यह मुद्दा चुनावी राजनीति का प्रमुख विषय बन जाता है। यदि ई-20 पर तथ्य, वैज्ञानिक अध्ययन और सार्वजनिक हित के संकेतों में रखकर चर्चा होती है तो इसका तबला बंध और नागरिक दोनों को मिलेगा। लेकिन यदि यह केवल राजनीतिक आग-बौल बनने पर तब सीमित रह जाता है, तो भूमि मुद्दा पीछे छूट जाएगा। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सरकार और विश्व दोनों समता के हित को सर्वोपरि रखते हुए संवाद, संवेदनशीलता और जनमत के साथ अपनी भूमिका निभाए।

नारायणोपनिषद् की मुख्य विशेषताएँ

नारायण से सवार रुद्र, अस्सुस और स्युषण
 हृदय प्रवृत्त हुए। नारायण से प्रेरित होकर,
 कोई अपने-अपने काम में शामिल हो
 जाता है जो एकतामय भगवान नारायण में से
 निकल आता है। यह त्रैलोक्य उपनिषद
 वर्णन है। १। नारायण ही ब्रह्मा है,
 नारायण ही निर्माता है, नारायण ही इन्द्र है,
 नारायण ही आकाश और पृथ्वी हैं। नारायण
 काल है। नारायण ही नाद है। नारायण ही
 त्वं (उपर) है। नारायण
 अथः (नीचे) हैं,
 नारायण ही बाहर हैं।
 नारायण ही स्थल हैं। जो
 काल में था और जो
 समय में होगा, वह सब
 नारायण ही हैं। वे स्थूल
 (द्रव्यमय), सूक्ष्म
 (दोषरहित),
 सूक्ष्म (विना किसी
 रूपात्मक) , शुद्ध
 रूपात्मक नारायण हैं।
 वे ही विष्णु हैं, वे ही विष्णु
 नारायण

[illegible]

वैसे, इसका स्वरूप परम प्रकाशमय और बिजली के समान है। ब्रह्ममय देवकीनंद भगवान श्री कृष्ण ही ब्राह्मण यानी ब्राह्मणों के आराध्य हैं। मधुसूदन, पुण्डरीकाक्ष और विष्णु- ये सभी अचूक और अज्ञानी हैं। हर आत्मा में केवल भगवान नारायण ही निवास करते हैं। ये सभी गुण के मूल (कारण-पुरुष) होने पर भी स्वयं गुण-रहित हैं। वे ही परम पुरुष हैं। पवित्र अक्षर ? के रूप में प्रकट होने

को जानता है, वह भी भगवान नारायण में अवतरित होता है। 77577 है भगवान! आप सत्य, निजी और आनंद के स्वरूप हैं। मेरी वाणी मेरे मन में स्थित हो और मेरा मन मेरी वाणी में स्थित हो। है प्रकाश के स्वामी! आप स्वयं को मेरे साथ स्तुत करें। हे मन और वाणी! आप मेरे लिए वैदिक ज्ञान के भंडार। मैंने जो ज्ञान सुना है, वह कभी मुझसे दूर नहीं हो गया। मैं सदैव श्रेष्ठ शब्द बोलूँ और

केवासि सत्य ही कहें। वह परम सत्य (ब्रह्म) मेरी और वही गुरु को खा करे। ७७ शांति, शांति शांति! ७७ भगवान शांति के स्वरूप हैं, वे तीन प्रकार के पदार्थ हैं—भौतिक (आधिभौतिक), दैवीय (आधिदैवीय) और आध्यात्मिक (आध्यात्मिक)। जो पूरी तरह से शांति करे (जो अन्तर्मन सिर्फ वाला है) (वही विहङ्गम जिससे सब लोकों को ऊपति होती है, वही महेश्वर का शरीर है। इसलिए हमारी आत्माओं के लिए भी उन्हीं के लिए हैं। इसलिए वह महेश्वर अन्त सिर्फ वाला है। इसी तत्व से), अन्त नेनों वाला है, जिससे सब लोकों का सृष्टि उत्पन्न हो रहा है, वही विहङ्गम, जगत को देने वाला, नारायण (जो जगत् के कारण पाँच तत्वों में विद्यमान है), स्वयं प्रकाशित करने वाला, अक्षर, सबका कारण, पवित्र और सुविमानों को प्राप्त होने वाला है, उसी ब्रह्म (महेश्वर) का ध्यान करना चाहिए।

सभी भौतिक श्रेणियों से ऊपर, वह परमात्मा अविनाशी, शाश्वत, सर्वव्यापी होने के कारण, ब्रह्मांड, दुनिया के कारण में स्थित होने के कारण नारायण है, और पाप और अज्ञान का नाश करने वाला होने के कारण हरि है; इसी तरह, अज्ञानी को जो कुछ भी दिखाई देता है, वह मूल रूप से परमात्मा ही है। वह परमात्मा इस ब्रह्मांड में रहता है यानी, अपने कामों के लिए इसमें (ब्रह्मांड में)।

शरण लेता है
मनिं बिश्वरूपार्थनोशन शिवायान्नो

पति पतिव्रत्याश्चनक्त शिवाच्युत
भगवान् का ध्यान करत चाहिये क्योंकि वे
जगत के पालक हैं, भगवान् क्योंकि वे पति
हैं, भगवान् क्योंकि वे आत्मा के नियंत्रक हैं,
भगवान् क्योंकि वे निरंतर और शक्तिशाली हैं,
भगवान् क्योंकि वे परम शुभ हैं, भगवान्
क्योंकि वे अपरिवर्तनीय हैं, भगवान् क्योंकि
वे नारायण हैं, भगवान् क्योंकि वे ज्ञेय
सिद्धांतों में सर्वोच्च हैं, भगवान् क्योंकि
वे महान ज्ञेय हैं, भगवान् क्योंकि वे जगत के
पालक हैं और इसलिए जगत से अलग हैं,
भगवान् क्योंकि वे ब्रह्मांड हैं, और भगवान्
क्योंकि वे श्रेष्ठ हैं, भगवान् क्योंकि वे
पारलौकिक हैं।

पुराणों में नारायण शब्द से जाने जाने वाले भगवान सत्य और ज्ञान आदि का सिद्धांत हैं, जो परम प्रकाश हैं। नारायण ही परमात्मा हैं। नारायण ही परम ब्रह्म हैं। नारायण ही सर्वोच्च हैं। वे ध्यात (वेदांत के रचयिता), ध्यान (परमात्मा के बारे में दृष्टिकोण) और पापियों के शत्रु हैं।

इस वर्तमान संसार में जो कुछ भी निकट जगत में देखा जाता है या दूर जगत में सुना जाता है, नारायण उत्पन्न भीतर और बाहर से व्याप्त हैं। (जैसे मुकुट, कंगन आदि आभूषणों का सोना, उत्पन्न भीतर और बाहर से व्याप्त है, वैसे ही नारायण हर जगह व्याप्त हैं। नारायण का स्वरूप असीम, विनाशरहित, निराकार, समस्त, सागर के समान विशाल, जगत का अंत और उसकी उत्पत्ति का कारण है। जैसे अंतःपंचद्वीपों वाले कमल के बीज के छिद्र का हृदय नदी की ओर होता है नाभि का निचला भाग स्थिति से दिसा होता है। अर्थात्

-संजय गोस्वामी

एकमात्र प्रभु, मनोरंजन-अभिव्यक्ति, विकास, अवर्णनीय और शुद्ध देव हैं। अ, उ, उर म इन तीन मात्राओं से यह प्रत्यक्ष भौतिक स्वरूप आनंदमय और ब्रह्ममय ही प्राप्त होता है। ये अलग-अलग हैं, लेकिन इन से तीन मात्राओं के अद्भुत रूप को ही हम कहा जाता है। इस ओम मंत्र का जाप करने से योगी-साधक जन्म-मृत्यु के बंधनों मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति ओम मंत्रोपासना या मंत्र का जाप करता है, वह वैकुण्ठ में जाता है। इसी वैकुण्ठ धाम को पुण्डरीक (चक्र-कलम) के रूप में जाना जाता है।

स इस साक्षात् अध्येन और भीर में इस
उपनिषद् के पाठ से रात में पाथ थोर जाते हैं।
दोनो साध्य-काठों (भीर और शाम) में
इस्का पाठ करने से साधक पापों से मुक्त हो
जाते हैं, यहाँ तक कि पिछले जन्मों के पापों
से भी। दो में सूर्य देव को और सेरुका पाठ
करने से मनुष्य पाँच महापापों (महापातक)
और छोटे पापों (उपपातक) से सदा के
लिए मुक्त हो जाता है। इससे पारों देवों के
पाठ का पुण्य प्राप्त होता है और नक्षत्र शरीर
प्राप्त पर भावान नायकन से साक्ष्य शश्वत
मिलन (सायन्य) पाठ होता है। जो इस मन

सबका कारण, परम और बुद्धिमानों को प्राप्त होने वाला है; उसी ब्रह्म (महेश्वर) का ध्यान करना चाहिए।

सभी भौतिक श्रेणियों से ऊपर, वह परमात्मा अविनाशी, शाश्वत, सर्वव्यापी होने के कारण, ब्रह्मांड, दुनिया के कल्याण में स्थित होने के कारण नारायण है, और पाप और अज्ञान का नाश करने वाला होने के कारण अक्षर है; इसी तरह, अज्ञानी को जो कुछ भी दिखाई देता है, वह मूल रूप से परमात्मा ही है। वह परमात्मा स्व ब्रह्मांड में रहता है यानी, अपने कामों के लिए हमें (ब्रह्मांड में)

आठ पंखुड़ियों वाले कमल के बीच के छिद्र का हृदय नीचे की ओर होता है नाभि का निचला भाग तिष्ठति से घिरा होता है। अर्जुन की माला ही ब्रह्माण्ड का संसार है। यह गर्दन के नीचे और नाभि के ऊपर एक वीर की दूरी पर स्थित है। इसमें ब्रह्माण्ड का आधार और प्रकाश की परंपरा से संपन्न परम ब्रह्म प्रकट होता है।

-संज्ञय गोरवामी

-संजय गोस्वामी

-8809 का हल

ख	त	क		न
ल	ह		र	वा
		छा	लि	स
छा	न		भ	
वि		श	रा	रा
द	र	क		ज
	ह		आ	न
ही	न		स	
र		स	न	म

लांजी में "पद्मेश"
इंटरनेट (ब्राडबैंड)
कनेक्शन के लिये संपर्क करें
Mo. 8319969927

कर्मगर्त

पोर्ट शाम तक आ भी एकर एक्कर भी हो जाय। कर्मगर्त में दलिया की पूरी भाज्यार्यकारणी बर्खास्त कर दी जाय। प्रेक्षा कार्यालय मंत्री जी पर के मुताबिक भारतीय मर्त में के प्रेक्षा अथय्य ब निवर्त में खण्डेलवाल के निर्देशन अथय्य विधानसभा उचुचाना प्रणामों की समीक्षा के लिए मर्मित की अनुशंसा के आधर्यकारणी जलता पोर्ट, जिला लले संघटन में जिलाध्यक्ष से लला पदाधिकारी, अथय्यसमिति, मंडल मोर्चा अथय्य विभाग समेत सारी ईन अनुशंसागत्य कारंदाय के ग कर दिया गया।

शुभमन की कप्तानी में श्रीलंका दोहरे पर पहुंची भारतीय टीम

राहुल ने वीडियो जारी किया, गीली पिच पर खेलते दिखे

कोलंबो। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका दौर पर पहुंच गयी है। भारतीय टीम को यहां मेजबान टीम के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गैल में खेला जाएगा। इस दौर पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा होगी क्योंकि उन्हें श्रीलंका के अनुभवी और युवा स्पिन गेंदबाजों का सामना करना पड़ेगा। इसे सीरीज से पहले भारतीय टीम के उप-कप्तान केएल राहुल ने एक वीडियो जारी कर अपनी तैयारियों के बारे में बताया है। इसमें साफ संदेश दिया है कि भारतीय टीम श्रीलंकाई हालातों से निपटने के लिए तैयार है।

राहुल ने अपने सोमेल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्हें नेट्स में एक अनोखे तरीके से अभ्यास करते देखा जा सकता है। मुंबई में हुए इस अभ्यास सत्र में राहुल ने जानबूझकर गीली पिच पर बल्लेबाजी का अभ्यास किया। इस विशेष तैयारी का

लक्ष्य श्रीलंका की स्पिन-अनुकूल पिचों पर मिलने वाले और रूक कर आने वाली गेंदों से निपटने के लिए अभ्यास करना था। यह दिखाता है कि भारतीय

बल्लेबाज श्रीलंकाई स्पिनरों की चुनौती को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने अपनी एग्रेसीव को मैदान पर उतारने से पहले ही मानसिक और तकनीकी रूप से

अपने को तैयार करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि ये यह दो मैचों की टेस्ट सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है क्योंकि यह विश्व टेस्ट

चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में अपनी जगह बनाने के प्रयासों को देखते हुए अहम है। भारतीय टीम को इसमें श्रीलंका को 2-0 से हराना होगा।

यहां के हालातों से निपटने के लिए भारतीय टीम ने एक विस्तृत योजना बनाई है। टीम अपने साथ चार नेट गेंदबाजों को श्रीलंका लेकर गई है, जिनका मुख्य काम बल्लेबाजों को लगातार स्पिन गेंदबाजी का अभ्यास कराना होगा। यह कदम भारतीय बल्लेबाजों को श्रीलंकाई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने और विभिन्न स्पिन आक्रामकों का सामना करने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगामी दिनों में यह देखा दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम इस नई रणनीति से कितना सफल रहती है। इस सीरीज की शुरुआत से पहले दोनों टीमों 7 गसत की एक अभ्यास मैच में हिस्सा लेंगी। इसका बाद पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक और दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक खेला जाएगा।

बीसीसीआई चयन समिति में हो सकता है बदलाव, अगरकर को हटाये जाने की संभावना

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इससे चयन समिति और प्रबंधन भी बच सकते हैं। वहां तक कि मुख्य चयनकर्ता के पद से अजीत अगरकर को हटाये जाने की संभावनाएँ भी बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्य चयनकर्ता अगरकर का कारकाल आगले महिने सितंबर, समाप्त हो रहा है और उसे आगले साल तक बच्ये जाने की संभावनाएं नहीं हैं। इससे ये संभावना उठता है कि अगरकर के बाद इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को कौन संभालेगा। अब तक जो नाम इससे लिए उपभरकर सामने आया है। वह है पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के प्रमुख वीरेंद्र सहस्रनाम का। अगरकर ने जुलाई 2023 में मुख्य चयनकर्ता का पद संभाला था।

उनके कार्यकाल में टीम इंडिया ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं जिसमें एशिया कप से लेकर चैम्पियंस ट्रॉफी और टी20 विश्वकप की जीत शामिल है। इन सफलताओं के बावजूद, उनके कार्यकाल की विस्तार की संभावना कम लग रही है। गौरतलब है कि बीसीसीआई ने उनके अनुबंध को पहले ही टीम महीने के लिए बढ़ाया था और 2027 विश्व कप तक विस्तार पर विचार कर रहा था। वहीं अब यह योजना मुश्किल में पड़ती दिख रही है। यह दिखाता है कि बोर्ड बड़े फैसलों की तैयारी में हैं, जो भविष्य की गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं।

उन्हें एक मजबूत प्रशासनिक और नए मुख्य चयनकर्ता के तौर पर उभरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह लंबे समय से भारतीय क्रिकेट के विकास में अहम भूमिका

निभा रहे हैं। एनसीए प्रमुख के रूप में, लक्ष्मण ने युवा प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें भारतीय धर्तू क्रिकेट संकेत और खिलाड़ियों के विस्तृत पूल को भी मजबूत करने में मदद मिली है। ऐसे में आगे के मुख्य चयनकर्ता को आमर दिया गया था, तब लक्ष्मण ने हो टीम की कमान संभाली थी। यह अनुभव उन्हें एक मजबूत प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता वाला उम्मीदवार बनाता है।

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य तेल गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी फिटनेस को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे हैं। इसी कारण वह बार-बार टीम से अंदर-बाहर होते रहे हैं। ऐसे में आगले साल होने वाले एकदिवसीय की भूमिका सफलतापूर्वक संभाली थी, और इससे पहले भी जब मुख्य चयनकर्ता को आमर दिया गया था, तब लक्ष्मण ने हो टीम की कमान संभाली थी। यह अनुभव उन्हें एक मजबूत प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता वाला उम्मीदवार बनाता है।

कि इसी दौरान भारतीय टीम ने कुल 29 एकदिवसीय मुकाबले खेले हैं, जिसका अर्थ है कि बुमराह ने इनमें से 26 महत्वपूर्ण मैचों को नहीं खेला है। 2023 एकदिवसीय विश्व कप फाइनल के बाद से ही हां बुमराह कुछ ही एकदिवसीय मैचों में ही मैदान पर दिखे हैं। ऐसे में यह संभावना उठता है कि क्या बुमराह अपनी इस सीमित उपलब्धता के साथ भारतीय टीम को 2027 का एकदिवसीय विश्व कप जीताने में सक्षम रहेंगे? याग ही, वर्कलोड मैनेजमेंट पर इनाम जोर दिए जाने के बावजूद उनकी पूरी फिटनेस हासिल न कर पाया भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

बुमराह की अनुपस्थिति

राष्ट्रमण्डल खेलों से गायब हुआ पाकिस्तानी मुक़ेबाज

रामली। राशमी राष्ट्रमण्डल खेलों से पाकिस्तान का एक मुक़ेबाज कुर्रुल्लाह गायब हो गया है। इस मुक़ेबाजे के गायब होने से पाक मुक़ेबाजी मांसमें को मुक़िलें बढ़ गयी हैं। पहला मासला नहीं है जब कोच पाक खिलाड़ी गायब हुआ है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले होते रहे हैं। इसी की लेकर पाकिस्तान ओपियन संघ का कहना है कि राष्ट्रमंडल खेलों में अपने मुकाबले में उतरे के बाद कुर्रुल्लाह टीम होस्ट से गायब हो गया था जिसके बाद से हो इसका कुछ पता नहीं चला है। हमारी को बात ये है कि इसका पासपोर्ट टीम मैनेजर के पास हो गया है। इसके बाद भी वह गायब हो गया। वहीं इससे पहले भी एक बार कुर्रुल्लाह खेलों में पाकिस्तान के दो मुक़ेबाज मुक़्तार बघेली और नज़ीरुल्लाह खान भीमिने गायब हो गए थे जबकि पासपोर्ट इन प्रमुख पाक गाय थे। पाक ओपियन संघ के एक अधिकारी के अनुसार कुर्रुल्लाह को शिया के लिए अहम कुर्रुल्लाह के कपरे में गये थे पर मुक़ेबाज नहीं रही था जबकि उसका सामान और निजी चीजें कपरे में भी थीं।

सीएन आइएन मूल के नील को अंडर-19 टीम में शामिल किया

सिडनी। भारत को जिस प्रकार 15 साल के वैभव सर्वश्री के तौर पर एक उपराला आसिया मिला है। वैया हो एक सितारा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) की भी मिल गया है। संयोग की बात ये है कि ये उपराला क्रिकेटर नील पटेल भी भारतीय मूल के हैं। युवा राशमी बल्लेबाज नील पटेल ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में अपनी प्रतिभा से सख को प्रभावित किया है। इसी कारण इस बल्लेबाज को अगला बनाया जाऊ। सितंबर से होने वाले भारत दौर के लिए ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम में शामिल किया गया है। नील को ऑस्ट्रेलिया के 16 सबसे होनहार और उपरते हुए क्रिकेटर्स की सूची में भी जगह मिली है जिससे उनकी असाधारण खेल क्षमता का अंजना होता है।

नील ने बहुत कम उम्र में ऑस्ट्रेलिया के धर्तू क्रिकेट और एज-रफ़ टूर्नामेंट्स में काफी अधिक रन बनाये हैं। उन्हें

ऑस्ट्रेलिया के सबसे रोमांचक और आक्रामक युवा बल्लेबाजी प्रतिभा में से एक माना जाता है। न्यू साउथ वेल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने अपनी ठोस तकनीक, होज पर गजब के संयम और लंबी पारियां खेलने की क्षमता के चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हुए पटेल ने सिर्फ 16 साल की उम्र में सुविर्धा बटोरी। उन्होंने एक कैलेंडर साल में 1,000 से ज्यादा रन बनाकर सिडनी प्रीमियर क्रिकेट फ़सट ग्रेड के लिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक बनने का कारनामा किया था। एक ओपनर के तौर पर इस उपरते क्रिकेटर को तेजी से खेलने का तरीका आता है। जिससे वह किसी भी प्राप में एक मूल्यवान खिलाड़ी बनाता है।

नील के लिए भारत का यह

दौर सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद खास है। भारतीय मूल के होज के कारण, भारत की टर्निंग पिचों पर खेलने उपरते लिए एक धर्तू और विश्वीर दोनों तरह का अनुभू अनुभव होगा। क्रिकेट जानकारों का मानना है कि उपमहाद्वीप की पिचों पर निपटारों का सामना करना किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के लिए नए अहमदाबाद और रासकोट की पिचों पर रन बनाने में सफल रहते हैं, तो उन्हें शीघ्र ही ऑस्ट्रेलिया की सीनियर टीम में अवसर मिला सकता है। ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 टीम अपने भारत दौर में एकदिवसीय और दो बार दिवसीय मैच भी खेलेगी। भारत का यह दौर नील के करियर को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा।

मुम्बई। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम जिस प्रकार से खेल रही है। उसको देखे हुए उसके विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 के फाइनल में पहुंचने की संभावना बेहद कम है। वर्तमान के पास आकाश अवसर है। चोपड़ा के अनुसार ये सही है कि भारतीय टीम दो बार की उपबिंबित रही है पर इस बार उसकी राह समाग असंभव नजर आ रही है। वहीं श्रीलंका के पास भारत के खिलाफ होने वाली आगामी परेलू सीरीज जीतकर शीर्ष चार में आग बनाने का अवसर है। भारतीय टीम 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में श्रीलंका का दौर करेगी। वर्तमान हालातों पर नजर डालें तो डब्ल्यूटीसी रैंकिंग में भारतीय टीम 48-150 फीसदी अंकों (पीसीटी)

के साथ पांचवें स्थान पर है, जिसने नौ मैचों में चार जीत और चार हार की हैं। वहीं, श्रीलंका 41.67 पीसीटी के साथ छठे स्थान पर है। चोपड़ा ने बताया कि श्रीलंका के लिए यह सीरीज निर्णायक



साबित हो सकती है। उन्होंने कहा, अगर सीर 2-0 से हारे हैं, तो हम सिर्फ 39 फीसदी अंक र रहेंगे और श्रीलंका 41.67 पर पहुंच जाएगा और चौथे नंबर पर आ जाएगा। अगर श्रीलंका भारतीय टीम 2-0 से हारता है तो वह टूर्ना में

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सीरीज 1-1 से डूई होती है, तो दोनों टीमों को कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह 48.48 पीसीटी और श्रीलंका 44.44 पीसीटी पर रहेंगे, जिससे उनकी मौजूदा स्थिति में कोई बड़ा

बदलाव नहीं आएगा।

आने वाली परेशानी पर भी प्रकाश डाला, जो उनके फ्यूचर में पहुंचने की राह को और परिष्कृत बनाएगा। उन्होंने कहा, आगे हमारे पास न्यूजीलैंड में 2 मैचों की सीरीज है, वहां जीतना मुश्किल है। अगर आगे एक भी मैच हारे हैं, तो आप 50 फीसदी अंक खो देंगे। यह एक मुश्किल सीरीज होगी और उसके बाद भारत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच हैं। भारत मुश्किल स्थिति में है। न्यूजीलैंड में भारत का रिकार्ड खराब रहा है, 2008/09 के बाद से उन्होंने वहां कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। भारत को खेले मैदान पर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संघर्ष करना पड़ सकता है, जैसा कि न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले साल मिली लगातार क्लीन स्वीप से स्पष्ट है।

आमर हालांकि शतक नहीं लगा पाये और 88 रनों को आउट हो गये। बाबर के आउट होने के बादपिछले क़म में साँझ धारा ने 30 रनों की महत्पूर्ण ग़ारी खेलकर को 387 रनों तक पहुँचने में मदद की।

इससे पहले, मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था।

इससे पहले, मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था।

इससे पहले, मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था।

बुमराह की खराब फिटनेस से उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर उठे सवाल

पिछले 970 दिन में सिर्फ तीन एकदिवसीय ही खेल पाये

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट टीम की इसी दौरान भारतीय टीम ने कुल 29 एकदिवसीय मुकाबले खेले हैं, जिसका अर्थ है कि बुमराह ने इनमें से 26 महत्वपूर्ण मैचों को नहीं खेला है। 2023 एकदिवसीय विश्व कप फाइनल के बाद से ही हां बुमराह कुछ ही एकदिवसीय मैचों में ही मैदान पर दिखे हैं। ऐसे में यह संभावना उठता है कि क्या बुमराह अपनी इस सीमित उपलब्धता के साथ भारतीय टीम को 2027 का एकदिवसीय विश्व कप जीताने में सक्षम रहेंगे? याग ही, वर्कलोड मैनेजमेंट पर इनाम जोर दिए जाने के बावजूद उनकी पूरी फिटनेस हासिल न कर पाया भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

बुमराह की अनुपस्थिति

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट टीम की इसी दौरान भारतीय टीम ने कुल 29 एकदिवसीय मुकाबले खेले हैं, जिसका अर्थ है कि बुमराह ने इनमें से 26 महत्वपूर्ण मैचों को नहीं खेला है। 2023 एकदिवसीय विश्व कप फाइनल के बाद से ही हां बुमराह कुछ ही एकदिवसीय मैचों में ही मैदान पर दिखे हैं। ऐसे में यह संभावना उठता है कि क्या बुमराह अपनी इस सीमित उपलब्धता के साथ भारतीय टीम को 2027 का एकदिवसीय विश्व कप जीताने में सक्षम रहेंगे? याग ही, वर्कलोड मैनेजमेंट पर इनाम जोर दिए जाने के बावजूद उनकी पूरी फिटनेस हासिल न कर पाया भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

बुमराह की अनुपस्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश बीमा नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल!

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, नई कारों और बाइकों के इंधनोरेस नियम भी बतले

नई दिल्ली। सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि जिने वाहनों का वैध थर्ड-पार्टी बीमा नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार को एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की जाटिस संजय करोल और जाटिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह निर्देश देते हुए नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी बीमा की अवधि भी बढ़ाने का आदेश दिया। कोर्ट के निर्देश के अनुसार, पेट्रोल पंपों को वाहन के बीमा रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। यदि किसी वाहन का थर्ड-पार्टी इश्योरेंस वैध नहीं पाया जाता है, तो उसे इंधन देने से इनकार किया जा सकता है। यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। इसके लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विनियामक प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नगरीय मिलकर तकनीकी ढांचा तैयार करेगा।

ऐसे होगी बीमा की जांच
पेट्रोल पंपों और प्रमुख सड़कों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे



लाए जाएंगे। ये कैमरे वाहन का नंबर प्लेट और थर्ड-पार्टी बीमा लेना होगा। अदालत ने कहा कि 2018 में लागू व्यवस्था के बावजूद देश में बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं, इसलिए यह बदलाव आवश्यक है।

नई गाड़ियों के लिए बदले नियम
सुप्रीम कोर्ट ने नई गाड़ियों के अनिवार्य थर्ड-पार्टी बीमा की अवधि बढ़ा दी है। नई कार अथवा 3 वर्ष के बजाय 4 वर्ष का थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य होगा। नई

बाइक/स्कूटी अब 5 वर्ष के बजाय 6 वर्ष का थर्ड-पार्टी बीमा लेना होगा। अदालत ने कहा कि 2018 में लागू व्यवस्था के बावजूद देश में बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं, इसलिए यह बदलाव आवश्यक है।

पुलिस के पास होगा रिमल-टाइम सिस्टम
कोर्ट ने राख्यों को निर्देश दिया कि पुलिस को ऐसे हैंडडल ड्रिवाइस

या मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए जाएं, जो संधी वाहन और आईआईटी डेटाबेस से जुड़े हों। इससे सड़क पर ही किसी भी वाहन का बीमा स्टेटस तुरंत जांचा जा सकेगा और आवश्यकता होने पर ई-चालान जारी किया जा सकेगा।

टोल प्लाजा पर भी बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने चुनिंदा कॉरिडोर पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन आधारित फी-फ्री टोलिंग सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया है, जिससे वाहन बिना रुके टोल पर कर सकें। विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत आंकों के अनुसार, देश में चल रहे करीब 56 प्रशांत वाहन बिना थर्ड-पार्टी बीमा के हैं। ऐसे वाहनों से दुर्घटना होने पर पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा मिलने में देर लग जाते हैं। मोटर वाहन अप्रतिभय को धारा 146 के तहत प्रत्येक वाहन के लिए थर्ड-पार्टी इश्योरेंस अनिवार्य है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति तथा उसकी संपत्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

दुष्कर मामलों की सुनवाई के लिए नई न्यायिक गाइडलाइन

अदालतों को संवेदनशील भाषा अपनाने के निर्देश

नई दिल्ली। दुष्कर और चीन उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायिक भाषा को अधिक संवेदनशील और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने नई न्यूडिशियल सेंसिटिविटी हैंडबुक जारी की है। 2026 में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद देश की सभी अदालतों में अपनाते निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने जो प्रमुख निर्देश दिए हैं उसके अनुसार, जज निर्णय देते समय पक्षित के चरित्र, पदान्ते, जीवनशैली या नैतिक धारणाओं के बजाय केवल उल्लेख्य साक्ष्यों और कानून के आधार पर फैसला करें। न्यायिक आदेशों और टिप्पणियों में ऐसी भाषा से बचा जाए जो पीड़ित को दोषी ठहराने, शर्मिंदा करने या पूर्वाग्रह दर्शाने वाली हो। लज्जा भंग, हवस, इज्जत, शर्म, पश्चिन्ता, बेवकूफ महिमा तथा प्रोसिक्यूटिव जैसे शब्दों के प्रयोग से परहेज करने को सलाह दी गई है। अदालतों को सम्मानजनक, तटस्थ और पक्षित-केंद्रित भाषा अपनाने पर जोर दिया गया है।

इस हैंडबुक को तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस ने की। समिति के अनुसार न्यायिक भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि निष्पक्ष और गरिमपूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण आधार है। यह गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के 10 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में तैयार की गई है। इससे पहले 2023 की जेडर स्टडीरिपोर्ट्स हैंडबुक की समीक्षा कर भारतीय सामाजिक संदर्भ के अनुरूप नई गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए गए थे। सुनवाई के दौरान भारत के तत्कालीन प्रथम न्यायाधीश सर्वेकार ने कहा था कि अदालतों को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए जो पीड़ित को भ्रमोभीत करें या शिकायत वाजस लेने का दबाव पैदा करें। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशों को संवेदनशीलता और पक्षित कानूनी अध्ययन के साथ निष्पक्ष लिलाने चाहिए। नई गाइडलाइन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चीन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया पूर्वाग्रह-रहित, सम्मानजनक और साक्ष्य-आधारित हो, ताकि पीड़ितों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत हो सके।

भारत के एफसीआरएर विधेयक पर अमेरिकी आपति, ईसाई समुदाय पर सीधा हमला

पर सीधा हमला

नई दिल्ली। भारत सरकार के प्रस्तावित विदेशी अंशदान (निविन्धन) संशोधन विधेयक-2026 पर अमेरिका ने आपति जारिर की है। रिपब्लिकन प्रतिनिधि राइली एम. मूर ने विधेयक को भारतीय ईसाई समुदाय पर सीधा हमला करार देकर चेतावनी दी है कि यदि विधेयक को इसी रूप में पारित किया गया, तब यह भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में गंभीर चिंगा का विषय होगा।

राइली मूर ने एएस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर कहा कि भारत में ईसाई समुदाय का इतिहास सदियों पुराना है, जब सेंट थॉमस द एपोसल ईसा मसीह के पुरुरूपान के दरशां बाद मालाबार पर आ गए थे। उन्होंने चिंत व्यक्त की कि इसके बावजूद, भारतीय संसद एफसीआरएर नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य चर्च और धार्मिक वैचरिटी संस्थाओं पर सख्त कानूनी नियमों का प्रसार करने का है। मूर ने कहा कि यह कदम ईसाई समुदाय की स्वायत्तता पर सीधा आघात है। कैथोलिक पुरुरान ने भी मूर पर राइली मूर के समर्थन में आवाज उठाई है।

प्लास्टिक के नोट अप्रैल-मई 2027 में आएंगे

नई दिल्ली। पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट अप्रैल साल अप्रैल-मई के बीच लांच होंगे। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक की मांनिटरिंग ऑफिसी की तीन दिन चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में कम वैल्यू के पॉलीमर करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। इनका मार्केट में सर्कुलेशन और इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पॉलीमर करेंसी नोट 30 साल से भी अधिक समय तक सफरतापूर्ण उपयोग में रहे हैं। भारत में कागजी नोट, विचित्र रूप 10, 20 और 50 रूपए के छोटे नोट, बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं या फटने लगते हैं। गवर्नर ने कहा कि पॉलीमर नोट आने से इनकी उम्र बढ़ेगी, पानी या ममी से ये खराब नहीं होंगे और बार-बार नोट छापने का सस्कारो खर्च भी कम होगा।

सूचना को लेकर भी सरकार ने कई कदमों की जानकारी दी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय फिलहाल उन हवाई पट्टियों का आकलन कर रहा है जहां निगमों व्यवस्था प्रचलित नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान होने वाले हारसों की जिम्मेदारी उड्डान प्रशिक्षण संस्थानों की होगी और सरकार उन्हें आवश्यक सहयोग देगी। विमान इंजन की बढ़ती कीमतों पर मंत्री ने कहा कि फिलहाल यह सस्कार के लिए चुनौती है, लेकिन इसे अस्थायी समस्या माना जा रहा है। यदि कीमतों में गंभीरता लंबे समय तक जारी रहती है तो सस्कार जरूरी कदम उठाने पर विचार करेंगे।

इसके अलावा सस्कार इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस जारी करने की तैयारी में है, जिससे लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक तेज और आसान बनाना जा सकेगा।

दो साल बाद सामने आईं श्रेष्ठ हसीना बोल्लो-बांलादेश लौटना चाहती हूं, शायद दिसंबर में जाऊंगी

नई दिल्ली। बांलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रेष्ठ हसीना केवि दो साल बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आईं। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वह वरुंडा माथ्यम से जुड़ी और अपनी बातें बोलीं। हालांकि, इस दौरान उनका कैमरा बंद रहा और केवल उनकी आवाज सुनाई दी। हसीना ने कहा कि उन्हें देश से दूर कर दिया गया, लेकिन वह अपने लोगों से कभी अलग नहीं हुईं। उन्होंने कहा कि वह बांलादेश वापस लौटना चाहती हैं और संभव है कि दिसंबर में अपने देश आएंगे।

अपने संकेपक के दौरान श्रेष्ठ राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने सदस्यों को स्पष्ट चेतावनी दी कि सदन के लेन में आने और प्लेकार्ड दिखाने जैसे गतिविधियां नियमों के विरुद्ध हैं तथा ऐसा करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई का जवाबती है। बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही पुनः शुरू होने पर सभापति ने सभी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वे अपनी-अपनी सीटों पर रहें और सदन की गरिमा बनाए रहें। उन्होंने कहा कि यदि कोई सदस्य इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसे बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए वे बाध्य होंगे।

सभापति की अपील के बावजूद विपक्षी सांसदों की नारेबाजी जारी रही। कई सदस्य प्लेकार्ड लेकर सदन के केंद्र तक पहुंच गए, जिसके कारण प्रमुख अतिथि और प्रमुखताओं के चलते काफी प्रभावित हुईं। इससे पहले भी लोकसभा में हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। मानसून सत्र के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों की लेकर संसद के दोनों सदन में लगातार गतिरोध बना हुआ है, जिससे विधायी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

2047 तक भारत में होंगे 3 हजार से ज्यादा विमान, 350 से अधिक एयरपोर्ट का लक्ष्य

नई दिल्ली। भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक बड़े विस्तार का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विमानन क्षेत्र का विजन साझा करते हुए कहा कि 2047 तक देश में 3 हजार से ज्यादा विमानों का बेड़ा और 350 से अधिक हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, आने वाले पांच वर्षों में भारतीय विमान बेड़े में 500 नए विमान शामिल किए जाएंगे। फिलहाल देश में करीब 860 विमान हैं, जबकि 1,640 नए विमानों की डिलीवरी भी आने वाले समय में होगी है। सरकार का जोर देश में विमानन से जुड़े प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करने पर भी है।

राम मोहन नायडू ने बताया कि 'भारत में प्रशिक्षण, भारत में उड्डान' पहल के तहत पायलटों और विमानन क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मीचार्यों को देश में ही प्रशिक्षण देते दो दिशा में काम किया जा रहा है। नए उड्डान प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। शुरुआत में प्रत्येक केंद्र में 60 से 70 प्रशिक्षण विमान होंगे, जिन्हें बाद में 110 से 120 तक बढ़ाया जा सकेगा।

सूचना को लेकर भी सरकार ने कई कदमों की जानकारी दी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय फिलहाल उन हवाई पट्टियों का आकलन कर रहा है जहां निगमों व्यवस्था प्रचलित नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान होने वाले हारसों की जिम्मेदारी उड्डान प्रशिक्षण संस्थानों की होगी और सरकार उन्हें आवश्यक सहयोग देगी।

विमान इंजन की बढ़ती कीमतों पर मंत्री ने कहा कि फिलहाल यह सस्कार के लिए चुनौती है, लेकिन इसे अस्थायी समस्या माना जा रहा है। यदि कीमतों में गंभीरता लंबे समय तक जारी रहती है तो सस्कार जरूरी कदम उठाने पर विचार करेंगे। इसके अलावा सस्कार इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस जारी करने की तैयारी में है, जिससे लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक तेज और आसान बनाना जा सकेगा।

इसके अलावा सस्कार इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस जारी करने की तैयारी में है, जिससे लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक तेज और आसान बनाना जा सकेगा।

एनआरआई को न्यूड कर थप्पड़ मारे

लुधियाना। लुधियाना के होटल रेडीसन ब्लू में कनाडा से आई दिल्ली की युवती के साथ पुरुष को कोशिश की गई। युवती ने रुम बुक कर भाई के अड्डे भविष्य के लिए पूजा करवाने के लिए एक व्यक्ती को बुलाना। उसने ओहो हो व्यक्ती हरकतें शुरू कर दी। उसने उसे कहा कि उसके अंदर दो भूत हैं, उन्हें तुरंत बाहर निकालने की जरूरत है। पनआरआर युवती भूत भाने के लिए तैयार हो गईं। आरोपी ने भूत भाने के नाम पर युवती के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी। युवती ने विरोध किया तो उसने इसे भूत भाने की प्रक्रिया बताया। कुछ ही पलों में आरोपी ने युवती के साथ रेप करने की कोशिश की। इस दौरान उसे न्यूड कर थप्पड़ मारे। युवती ने आरोप को ब्युक्तिकर रूप से बाहर धकेला और उसके बाद पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अभी फरार है।

छात्र दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट नरम, आयोजकों की जवाबदेही पर याचिकाकर्ता की मांग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में युवाओं पर कठोर कार्रवाई न करने का संकेत दिया है, बल्कि उन्हें समझाने और सही सलाह देने का बात करी है। हालांकि, एक याचिकाकर्ता ने इसतरह के प्रदर्शनों के आयोजकों को जवाबदेही तय करने की पुर्तजारी मांग की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह इस याचिका पर अन्य लिखित याचिकाओं के साथ सुनवाई करेगा।

याचिकाकर्ता मनीष सोलंकी की ओर से पेश वकील सैयद रिजवान अहमद ने तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष दलील दी कि जहां केंद्र सरकार और पुलिस को जिम्मेदारी तय की जा रही है, वहीं आयोजकों के प्रति उदासी बर्ती जाती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोजकों ने पुलिस को दिए

वादे दोषी और संसद की ओर उध भड़ो कर भेजा। अहमद ने कहा कि अगर उन दिन 500 लोग भी लोकतंत्र के मंदिर में घुस जाते, तब पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती और स्थिति भयावर होती। उन्होंने कहा कि संसद कोतार मार्च के आयोजक आज भी भड़काने वाले बयान दे रहे हैं और स्थिति शांत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश सर्वेकार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायालय छात्रों पर कठोर कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। पीठ ने जो प्रक्रिया दी युवाओं को समझाना और सही सलाह देना चाहिए, क्योंकि आक्रामक कार्रवाई स्थिति को और बिगाड़ सकती है। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील अहमद

फिलहाल नहीं घटेगी लोन की ईएमआई महंगाई से जंग जारी रहेगी, आरबीआई ने रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा

महंगाई के अनुमान को

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार तीसरी समीक्षा बैठक में रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे कृषि हो होना लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें तथा ईएमआई में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने तीन दिवसीय एमपीसी बैठक के बाद कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की अनिश्चितता और वैश्विक के दबाव को देखते हुए फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है।

मल्होत्रा ने पॉलिसी का एलेन करते हुए कहा कि जुलाई के पहले हमने से वैश्व परिस्थिति में संकेत के हफ्ते से बढने से ऊनी की कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ा है और सर्वादा जेन को लेकर अनिश्चितता फिर से पैदा हो गई है। लगातार चली हुई वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद, फरेल आर्थिक गतिविधियों ने मजबूती दिखाई है, जैसा कि पहली तिमाही के लिए उपलब्ध हाई-प्रोसेसि ईडीकेटर्स से पता

चला। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्त वर्ष 2027 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का

महंगाई के अनुमान को

अनुमान बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया है, जो पिछले अनुमान से 10 बेसिस प्वाइंट्स ज्यादा है। उन्होंने बताया कि पहली तिमाही में देश की ग्रोथ 7 फीसदी रहने का अनुमान है। जबकि दूसरी तिमाही में 6.4 फीसदी रह सकती है। जबकि तीसरी तिमाही में ग्रोथ अनुमान 6.5 फीसदी देने का मिल सकता है। चौथी तिमाही में देश की ग्रोथ का अनुमान 6.8 फीसदी रहने का अनुमान है।

पहली तिमाही का कैड सरलत

इस साल अप्रैल-मई के दौरान भारत के करंट अकाउंट में 2.8 बिलियन डॉलर का सरफस (अधिशेष) दर्ज किया गया, जिसका मुख्य कारण सर्विस ईड और रमिटेड (विदेश से भेजी गई रकम) की अड्डे प्रतियोगिता है। पहली तिमाही में, मर्चेंडाइज ईडी डेफिसिट (बतु वयुवा घाटा) बढ़कर लगभग 86 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में लगभग 69 बिलियन डॉलर था। इसका मुख्य

भ्रष्टाचार और अवैध कमीशन मामले में कारोबारी डेबेर को मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने छतीसगढ़ राज्य विधान निगम लिमिटेड (सीएसएनएल) से जुड़े भ्रष्टाचार और अवैध कमीशन गिरेह के मामले में कारोबारी अमर देबर को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी। सीजेआई सर्वेकार, न्यायाधीश जॉनमिया बाबरी और न्यायमूर्ति जी मल्लिक की पीठ ने जमानत की शर्त के तौर पर देबर को जेलीसाइट से बाहर रहने और प्रकृष्टे की सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद होने का निर्देश दिया। देबर को यह भी निर्देश दिया कि अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह जहां रहे, उन पक्ष का निवेदन कोर्ट को उपलब्ध कराए। मॉडिया रिपोर्ट के मुताबिक छतीसगढ़ हाइकोर्ट ने 13 मई को देबर को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोप बात संवैधानिक निगम के भीतर "गहरे और व्यवस्थित भ्रष्टाचार के नेटवर्क" की ओर संकेत करते हैं।

समलैंगिक अधिकारों पर केंद्र सरकार की सुस्ती से शक्ति थरूर खफा

दो साल से नहीं हुईं हाई-पावर कमेटी की बैठक

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र भले ही हंगामे की भेंट खट रहा हो, लेकिन सरकार सांसद शक्ति थरूर ने अपने अत्याधिक प्रश्नों के लिखित जवाब मिलने की बात कही। उन्होंने केंद्र सरकार के इसतरह के एक जवाब पर गहरी नाराजगी जारिर की है। थरूर के अनुसार, राज्य सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फराले के बाद एलजीसीआरएएर एलस समुदाय के अधिकारों को सुरक्षा दिलाने हाई-पावर कमेटी की पुनः तयनाम रहने को उम्मांग करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार में न्यायिक क्रांति जड़ों की चिंगाओं को दूर करने और इस समुदाय के नागरिकों के लिए सार्वक आधिकार सुनिश्चित करने का कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है। कारीस संसद व बताया कि कमेटी का गठन हुए दो साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन इसकी सिर्फ दो बैठकें हुई हैं। इसकी आखिरी बैठक भी दो साल पहले हुई थी और तब कोई सिफारिश या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। कारीस तब थरूर ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए अंतरिम उपाय कभी भी सार्वक कानूनी सुधारों का विकास नहीं हो सके।

